वर्ष 13 • अंक 39 • 8 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

सोमवार 6 अप्रैल 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 3

आईआईएम में गार्टनर ने रद्द की नियुक्ति की पेशकश

क्रिस गोपालकृष्णन ▸▸ पृष्ठ 2

निवेशकों को निवेश दोगुना करने की जरूरत

एक नज़र

सोमवार और शुक्रवार को बंद रहेंगे शेयर व जिंस बाजार

इस हफ्ते बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिंस वायदा बाजार और मुद्रा विनिमय बाजार सोमवार को महावीर जयंती और शुक्रवार को गुड फ्राइडे पर बंद रहेंगे। इसके साथ ही सराफा और प्रमुख थोक बाजारों में भी अवकाश रहेगा। सप्ताह के बाकी दिनों में सामान्य कामकाज होगा।

मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों और पूर्व राष्ट्रपति से की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी सहित कई नेताओं से कोरोनावायरस महामारी की स्थिति पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि मोदी ने समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, द्रमुक के एमके स्टालिन और शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल सहित कई नेताओं से बातचीत की। मोदी ने घातक कोविड-19 से जुड़े मुद्दों पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा से भी चर्चा की। पृष्ठ 8

बीमा प्रीमियम भुगतान पर और 30 दिन की मोहलत

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का और समय दे दिया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू बंदी के मद्देनजर नियामक ने यह कदम उठाया है। ऐसे जीवन बीमा पॉलिसीधारक जिनकी नवीकरण की तारीख मार्च और अप्रैल में पड़ती है, उन्हें प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। बीमा नियामक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों और तीसरा पक्ष मोटर बीमा के नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पहले ही अतिरिक्त समय दे चुका है।

हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन दवा निर्यात पर पाबंदी और सख्त

सरकार ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन के निर्यात पर पाबंदी और सख्त कर दी है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयों को भी रोक के दायरे में शामिल कर दिया गया है। इस दवा के निर्यात पर 25 मार्च से ही रोक है, लेकिन कहा था कि कुछ भंडार को मानवीय आधार पर भेजने की अनुमति दी जा सकती है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। मलेरिया की इस दवा का इस्तेमाल अब कई जगह कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में किया जा रहा है। पृष्ठ 4

एयर डेक्कन ने कर्मियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा

क्षेत्रीय विमानन कंपनी एयर डेक्कन कोरोना वायरस संकट की वजह से पैदा हुए दबाव को नहीं झेल पा रही है और अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की है। साथ ही उसने सभी कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया है। कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सरकार ने देश में 21 दिन का प्रतिबंध लगा रखा है। इस राष्ट्रव्यापी बंदी से विमानन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एयर डेक्कन के मुख्य कार्याधिकारी अरुण कुमार सिंह ने कर्मचारियों को भेजे ई-मेल में कहा कि मौजूदा घरेलू और वैश्विक मुद्दों की वजह से नागर विमानन महानिदेशालय ने 14 अप्रैल तक सभी वाणिज्यिक उड़ानें बंद करने का निर्देश दिया है। ऐसे में एयर डेक्कन के पास अगले नोटिस तक परिचालन बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पृष्ठ 2

आधार को जन्मतिथि का प्रमाण मानेगा ईपीएफओ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खाते के केवाईसी के अनुपालन को सुनिश्चित करने को लेकर अपने अंशधारकों की जन्म तिथि में सुधार के लिए आधार कार्ड को वैध साक्ष्य मानेगा तथा उसे ऑनलाइन स्वीकार करेगा। श्रम मंत्रालय ने रविवार को कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता बढ़ाने के लिए ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किया है।

आज का सवाल

क्या 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हटाना सही कदम होगा

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**

आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या उद्योगों को मिलना चाहिए प्रोत्साहन पैकेज? हां **32.80%** नहीं **67.20%**

ज्यादा उधारी जुटा सकते हैं राज्य

केंद्र ने राज्यों को पूरे साल की 50 फीसदी उधारी अप्रैल में लेने की अनुमति दी

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 5 अप्रैल

- उधारी के बारे में आरबीआई से चर्चा करेंगे राज्य
- संसाधनों की कमी से जूझ रहा है केंद्र
- आरबीआई कैलेंडर के मुताबिक अप्रैल में 55 हजार करोड़ रुपये उधार लेंगे राज्य
- इस अनुमान से ज्यादा उधार ले सकते हैं राज्य
- विश्लेषकों के मुताबिक 3 लाख करोड़ रुपये उधार ले सकते हैं राज्य

कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई असाधारण परिस्थिति के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 में अपनी कुल उधारी जरूरतों का 50 फीसदी तक अप्रैल में ही लेने की अनुमति दे दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड को सूत्रों से यह जानकारी मिली है।

घटते राजस्व के कारण केंद्र के पास भी संसाधनों की कमी हो गई है जिसके कारण ऐसा कदम उठाना जरूरी हो गया था। संसाधनों की कमी के कारण केंद्र विभिन्न मदों में राज्यों के बकाये का भुगतान नहीं कर पा रहा है। इसमें केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा और अन्य अनुदान शामिल हैं। साथ ही विभिन्न राज्य वित्तीय पैकेज मांग रहे हैंए लेकिन केंद्र के पास इसके लिए संसाधनों की कमी है।

एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा, 'राज्यों को 2020-21 के लिए उनकी उधारी सीमा का 50 फीसदी तक हिस्सा अप्रैल में उधार लेने की अनुमति दे दी गई है। अगर वे अपनी कुल उधारी का आधा हिस्सा अग्रिम लेना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं।' उन्होंने साथ ही कहा कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो केंद्र राज्यों के लिए कुल उधारी सीमा में छूट देने पर भी विचार करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 31 मार्च को राज्यों के लिए अप्रैल-जून के लिए सांकेतिक उधारी कैलेंडर और केंद्र के लिए अप्रैल-सितंबर का कैलेंडर जारी किया था। लेकिन उससे पहले ही केंद्र ने राज्यों को यह अनुमति दे दी थी। अधिकारी ने कहा कि 50 फीसदी की सीमा के भीतर राज्य कितना उधार लेना चाहते हैं। यह राज्यों और आरबीआई पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा, 'हर राज्य आरबीआई के साथ चर्चा के बाद यह फैसला करेगा कि उसे कितना उधार लेना है। भविष्य में ब्याज भुगतान में कितनी देनदारी चाहते हैंए बॉन्ड बाजार में उनकी प्रतिभूतियों की कितनी मांग है।' सामान्य स्थिति में राज्यों की राजकोषीय सीमाओं से भी उनकी उधार लेने की क्षमता का निर्धारण होता है। राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन की सीमाएं अब भी लागू हैं लेकिन केंद्र और राज्यों के अधिकारियों का कहना है कि यह सामान्य समय नहीं है।

आरबीआई द्वारा अप्रैल-जून तिमाही के लिए जारी राज्यों के सांकेतिक कैलेंडर के मुताबिक राज्यों के इस अवधि में 1.27 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का अनुमान है। इसमें से करीब 55,225 करोड़ रुपये की उधारी अप्रैल में लिए जाने की उम्मीद है। इस तरह यह तिमाही के कुल अनुमान को पार कर जाएगी। अधिकारी ने कहा कि आरबीआई के मुताबिक यह सांकेतिक कैलेंडर है। अमूमन राज्यों के अनुरोध पर केंद्रीय बैंक का रुख उदार होता है। इसलिए वे ज्यादा उधार ले सकते हैं।

हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक अनुमान मौजूद नहीं है कि राज्य वित्त वर्ष 2021 में कुल कितना उधार लेंगे क्योंकि सभी राज्यों ने अभी बजट पेश नहीं किया है। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष के मुताबिक यह राशि 7 लाख करोड़ रुपये हो सकती है। उन्होंने कहा, 'वित्त वर्ष 2020 में कुल उधारी 6.40 लाख करोड़ रुपये थी। मौजूदा असाधारण स्थिति को देखते हुए इस साल राज्यों की कुल उधारी इससे अधिक रह सकती है। हर साल सामान्य स्थिति में राज्यों की सकल उधारी में 10 फीसदी का इजाफा होता है। अगर हम इसके आधार पर देखें तो इस बार यह आंकड़ा 7 लाख करोड़ रुपये रह सकता है।

घोष के अनुमान को मानें तो अगर राज्य अपने पूरे साल की जरूरत का 50 फीसदी अप्रैल में लें तो यह राशि 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। केंद्र ने इस महीने 79,000 करोड़ रुपये की राशि उधार लेने की योजना बनाई है। इस तरह अप्रैल में सरकार कुल 3.8 लाख करोड़ रुपये उधार ले सकती है जिससे प्रतिफ ल पर भारी असर हो सकता है।

एनपीए पर छह महीने की मोहलत!

रघु मोहन
मुंबई, 5 अप्रैल

- एनपीए के वर्गीकरण के लिए बढ़ाई जा सकती है 90 दिन की अवधि
- दुरुपयोग रोकने के लिए होंगी कई शर्तें
- मार्च 2021 से फिर लागू होंगे नए नियम
- दबावग्रस्त या एनपीए खातों का होगा पुनर्निर्धारण
- नाबार्ड और सिडबी से पुनर्वित्त हो सकता है महंगा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्त मंत्रालय बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के वर्गीकरण की अवधि में छूट देने के मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक 90 दिन तक मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं होने पर आवंटित ऋण एनपीए बन जाता है लेकिन इस अवधि को बढ़ाकर 180 दिन किया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2019 तक बकाया राशि को दबावग्रस्त या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए गए खातों का डाउनग्रेड किए बिना पुनर्निर्धारण और 18 से 24 महीने की न्यूनतम पुनर्भुगतान अवधि के साथ नए वित्त पोषण पर विचार किया जा सकता है। साथ ही नए कर्ज के लिए बैंकों द्वारा पूर्व शर्त के रूप में अतिरिक्त रेहन के आग्रह को भी आसान बनाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि अगर एनपीए वर्गीकरण के लिए परिसीमन अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन की जाती है तो इसमें कई तरह की शर्तें जोड़ी जा सकती हैं ताकि इसका दुरुपयोग न हो। इसमें ऋण शुरू और बंद होने की तारीख का उल्लेख हो सकता है और 2021 के खत्म होने पर यह फिर 90 दिन की पुरानी अवधि में लौट आएगा। साथ ही ऐसा अर्जित ब्याज, जो 1 जनवरी, 2020 के बाद न मिला हो, उसे 1 अक्टूबर से मार्च 2021 के अंत तक छमाही किस्त में चुकाने की अनुमति दी जा सकती है। इससे संभावना है कि एनपीए के वर्गीकरण के लिए परिसीमन अवधि 180 दिन तक बढ़ाई जा सकती है।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

संकट के बाद की तैयारी में जुटी फर्में

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 5 अप्रैल

- घर से काम को मिली सफलता के बाद कार्यालय सीमित करने पर विचार
- फैक्टरियों में स्वचालित गतिविधियों पर अधिक जोर
- खर्च कम करने के लिए स्थानीयकरण पर जोर
- सेवाएं अधिक सुरक्षित बनाने की रणनीति
- फैक्टरियों में थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य करना

कोरानावायरस संकट के बीच कंपनियों ने भविष्य की रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया है। वाहन उद्योग के लिए पेंट बनाने वाली जापान की कंपनी निप्पॉन पेंट्स अपनी कारोबारी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। मारुति सुजूकी और टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक हैं।

गुड़गांव की यह कंपनी कोविड-19 के दौरान घर से कार्य करने के नए चलन को मिली सफलता देखेकर चकित है। इससे उत्साहित होकर कंपनी ने मुंबई में अपना बिक्री कार्यालय बंद करने का निर्णय लिया है और अब अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की हिदायत देने के बारे में सोच रही है। कंपनी अपने गोदामों की संख्या भी कम करने पर विचार कर रही है। देश में अपनी तीन फैक्टरियों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए कंपनी पेशेवर कंपनियों की सेवाएं लेना चाहती है। कर्मचारियों के बीच आपसी संपर्क कम रखने (सोशल डिस्टेंसिंग) के लिए कंपनी अलग-अलग पालियों में उन्हें बुलाना चाहती है। कंपनी में अध्यक्ष-ऑटोमोटिव रीफिनिशेस ऐंड वूड कोटिंग्स, शरद मेहरोत्रा कहते हैं, 'इसमें कोई शक नहीं कि कोविड-19 संकट के बाद कंपनियों के काम-काज के तरीके में खासा बदलाव आ जाएगा।'

भारत में कंपनी जगत के शीर्ष प्रबंधक कोविड-19 संकट की धार कमजोर होने के बाद के हालात में अपनी कारोबारी रणनीतियों, उत्पादों और मानक परिचालन नियमों में बदलाव करने के लिए ई-मेल और वीडियो कॉल का सहारा ले रहे हैं।

मारुति सुजूकी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा, 'यह पूरी कवायद लॉकडाउन खत्म होने तक नहीं हैं। दरअसल हम अपने कर्मचारियों को कई स्वास्थ्य एवं बचाव उपायों के साथ एक पूरी तरह अलग परिचालन प्रक्रिया के लिए तैयार कर रहे हैं। यह रणनीति दीर्घकाल के लिए तैयार हो रही है।'

कंपनियां यह मानकर चल रही हैं कि उन्हें हालात में सुधार के बाद सरकार से कुछ अनिवार्य निर्देश आ सकते हैं। कंपनियां पहले से ही इनकी तैयारियों में जुट गई हैं और वे थर्मल स्कैनर (शरीर का तापमान मापने वाला उपकरण) और सफाई एवं स्वच्छता पर विशेष जोर देने की तैयारी कर रही हैं।

वे अन्य अहम बदलावों पर भी विचार कर रही हैं। इनमें कोविड-19 संकट कमजोर होने या खत्म होने पर स्वचालन एवं स्थानीयकरण जैसे उपाय शामिल हैं। इस बारे में वाहन उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, 'रोजगार के लिहाज से यह अच्छी खबर नहीं है, लेकिन स्वचालन बढ़ने से उत्पादकता में इजाफा होगा और कार्यशैली में अधिक लचीलापन आएगा।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

औसतन 4 दिन में दोगुना हो रहे कोरोना के मामले

सरकार ने रविवार को देश भर के सभी जिलों के अधिकारियों को चिकित्सा उपकरण और दवाएं बनाने वाली इकाइयों का सुगम परिचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इससे एक दिन पहले सरकार ने डायग्नॉस्टिक्स किट के निर्यात पर रोक लगा दी थी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 का संक्रमण हवा से नहीं फैलता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तबलीगी जमात से जुड़े आठ मलेशियाई नागरिकों अवैध तरीके से देश से भागने की कोशिश करते पकड़ा गया है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 472 नए मामले सामने आए हैं जबकि 15 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 3,577 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और कुल 83 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कुछ खबरों के मुताबिक संक्रमितों की संख्या 3,624 हो गई है और 106 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस दौरान 284 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में 4.1 दिन में कोविड-19 के मामले दोगुने हो रहे हैं लेकिन तबलीगी जमात के मामले अगर नहीं होते तो यह आंकड़ा 7.4 दिन का रहता। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 503 हो गई है। इस बीच, दुनिया भर में 12 लाख से ज्यादा लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हुए हैं और 65,600 से अधिक की मौत हो चुकी है। *एजेंसियां*

दीये जलाकर दिखाई एकजुटता

फोटोः पीटीआई

कोलकाता के जेएन रॉय हॉस्पिटल की नर्सों ने कोरोनावायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए प्रधानमंत्री की अपील पर जलाए दीये और मोमबत्तियां।

धारावी पर मंडराया कोरोना का स्याह साया

एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में अत्यधिक घनी आबादी और साफ-सफाई बनी बड़ी चुनौती

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 5 अप्रैल

फोटो : विवेट सुजन पिंटो

- जनसंख्या घनत्व **2.70** लाख प्रति वर्ग किलोमीटर
- धारावी में कुल **7** वार्ड आते हैं
- **5,000** रुपये प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय
- प्रति परिवार **5** से **7** लोग
- अब तक कोविड के **5** मामले, **1** की मौत

सड़कें सूनी हैं, दुकानें बंद हैं और कुछ इलाकों की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में कर्फ्यू जैसा माहौल है, वहीं मुंबई के बाकी हिस्से में भी लॉकडाउन है। कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों की वजह से देश की वित्तीय राजधानी में 613 हेक्टेयर में बसी यह बस्ती वायरस रोकने की मुहिम के केंद्र में आ चुकी है।

धारावी इलाके में कोरोना संक्रमण के अब तक पांच मामलों की पुष्टि हुई है जिनमें से बुधवार को 56 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। शनिवार को एक 30 वर्षीय महिला और 48 वर्षीय व्यक्ति के संक्रमित होने का मामला सामने आया। अब डर इस बात का है कि यहां मामले ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि यहां की झुग्गियों और जर्जर घरों में बहुत सघन आबादी है और वे इस वक्त बिना किसी आमदनी और सीमित भोजन पर गुजर-बसर कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी स्वीकार किया कि धारावी की जनसंख्या के घनत्व और वहां के रहने वाले लोगों की तंगहाली को देखते हुए सरकार की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने बताया, 'हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि धारावी में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन हो। हम भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं देते हैं लेकिन यह आसान नहीं है। वहां जगह की कमी है, लोग गरीब हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। निश्चित रूप से चुनौतियां बड़ी हैं।'

गैर-सरकारी संगठनों के अनुमान के मुताबिक धारावी में एक परिवार की औसत मासिक आमदनी 5,000 रुपये से कम है। मुंबई के सात वार्डों में फैले धारावी की आबादी 15 लाख है जिनमें से करीब 5.10 फीसदी लोग लॉकडाउन की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने गृह शहर वापस जा चुके हैं। धारावी के कपड़ा व्यवसायी संजीवन जायसवाल बड़ी मुश्किल से अपनी मामूली बचत से लॉकडाउन समाप्त होने तक का खर्च चलाने की कोशिश कर रहे हैं। धारावी में ओएनजीसी कार्यालय के पास उनकी दुकान अभी बंद पड़ी है। उन्हें अपनी पत्नी, दो बेटों और बहू सहित अपने परिवार की सुरक्षा का डर है जो दुकान के ऊपर करीब 200 वर्गफुट की छोटी सी जगह में रहते हैं। उन्होंने एक सस्ता सा मास्क लगाया हुआ है और उन्हें घर से बाहर सिर्फ इसकी बदौलत ही सुरक्षित रहने का अहसास होता है। वह कहते हैं, 'मैं उन्हें घर से बाहर कदम नहीं रखने देता। अगर किराने का सामान लाना है तो मैं लाता हूं। हमारे पास हाथ साफ रखने के लिए सैनिटाइजर और हैंडवॉश नहीं है। हम साबुन की छोटी टिकिया पर ही निर्भर हैं।'

धारावी में रहने वाले समाजसेवी अनिल शिवराम कासारे कहते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई सार्वजनिक शौचालय की है जिसके लिए रोज संघर्ष करना पड़ता है। वह कहते हैं, 'धारावी में 1,500 सार्वजनिक शौचालय हैं। यह यहां रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हमें इसका ही इस्तेमाल करना होगा। कोरोनावायरस के फैलने का खतरा इस बस्ती में हर जगह मंडरा रहा है।' (शेष पृष्ठ 8 पर)

संक्षेप में

ओएनजीसी ने भेजा रॉयल्टी कम करने का अलर्ट

तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी ने गैस की कीमत में भारी कमी के बीच सरकार को त्राहिमाम का संदेश भेजा है। कंपनी ने करों में कमी और गैस की कीमत तय करने और बेचने की आजादी मांगी है ताकि उसका कारोबार ठीक से चल सके। कंपनी का कहना है कि देश में पैदा खनिज गैस का दाम कम होने से उसके लिए कारोबार चला पाना कठिन हो गया है और इसका उसकी निवेश योजनाओं पर असर पड़ सकता है। कंपनी के इस आग्रह की सीधी जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 20 डॉलर प्रति बैरल नीचे तक आ चुकी हैं। *भाषा*

भारत में इटियॉस, कोरोला एल्टिस की बिक्री बंद

जापान की वाहन कंपनी टोयोटा ने भारत में इटियॉस शृंखला और कोरोला एल्टिस की बिक्री बंद कर दी है। कंपनी ने बेहतर प्रौद्योगिकी वाले नए उत्पाद लाने के लिए अपने संयंत्रों में उत्पादन क्षमता को खाली करने के लिए यह कदम उठाया है। जापान की वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टोयोटा और किर्लोस्कर समूह के संयुक्त उद्यम टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने 2010 में इटियॉस सिडैन पेश की थी। 2011 में कंपनी ने इसका हैचबैक संस्करण इटियॉस लिवा उतारा था। कंपनी घरेलू बाजार में इटियॉस के 4.48 लाख वाहन बेच चुकी है। *भाषा*

छंटनी की चिंता पर सरकार की नजर

मुख्य श्रम आयुक्त ने स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को पत्र लिखा, वेतन कटौती न करने का आग्रह

सोमेश झा और अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 5 अप्रैल

केंद्र सरकार देश में मौजूदा संकट के बीच कामगारों की पेशेगत समस्याएं निपटाने की मुहिम में लगी हुई है। देश में लॉकडाउन के बीच कर्मचारियों की छंटनी और उनके वेतन में कटौती से जुडी चिंताओं के बीच अधिकारी नियोक्ताओं से लगातार संवाद कर रहे हैं।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाले मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को पत्र लिखा है और उन्हें केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने के लिए कहा है। कोरोनावायरस का संक्रमण तेजी से फैलने के बाद भारत सहित दुनिया भर में लोगों की आवाजाही थम गई है। घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उडानों पर प्रतिबंध से विमानन क्षेत्र पर सर्वाधिक असर हुआ है।

किफायती विमानन सेवा देने वाली स्पाइसजेट ने कर्मचारियों के मार्च महीने के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, कंपनी ने 25 से 31 मार्च की अवधि के लिए बिना वेतन अवकाश देने की घोषणा की थी। कंपनी के इस निर्णय के बाद इस विमानन कंपनी के कर्मचारियों ने नई दिल्ली और विजयवाड़ा के क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों से शिकायत की है।

सरकार ने कई बार कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही सरकार ने कंपनियों को कर्मचारियों की छंटनी करने से भी परहेज करने के लिए कहा है। केंद्रीय श्रम आयुक्त ने 2 अप्रैल को स्पाइसजेट को लिखे पत्र में कंपनी से पूछा है कि उसने सरकार के दिशा-निर्देशों पर क्या कदम उठाए हैं। दूसरी तरफ विजयवाड़ा में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ने लॉकडाउन के दौरान वेतन में कटौती को सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन बताया है और कंपनी प्रबंधन के साथ इस मामले को उठाया है। इससे जुडे दस्तावेज की बिजनेस स्टैंडर्ड ने अध्ययन किया है। स्पाइसजेट ने एक आधिकारिक बयान में बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि विभिन्न राज्य सरकारों ने परामर्श पत्र जारी किए हैं और इन्हें ध्यान में रखते हुए हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कंपनी ने किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की है। कंपनी ने किसी भी अस्थायी या अनुबंध पर काम करने वाले लोगों के वेतन में कटौती नहीं की है।

- 20 मार्चः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कंपनियों से वेतन नहीं काटने की अपील की
- 29 मार्च : गृह मंत्रालय ने सभी कंपनियों को लिखा पत्र, लॉकडाउन के दौरान बिना कटौती के समय पर वेतन भुगतान करने के लिए कहा
- 30 मार्चः मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों को कर्मचारियों की शिकायतों का तत्परता से समाधान करने का दिया निर्देश
- 04 अप्रैलः ईपीफओ ने संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कर्मचारियों की छंटनी रोकने और वेतन नहीं काटने की अपील की

कंपनी ने कहा कि लॉकडाउन की घोशणा के बाद विमानन उदयोग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्पाइसजेट के खिलाफ कर्मचारियों के एक समूह ने शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने की गुजारिश की है। इन कर्मचारियों को उनकी नौकरियां जाने का डर सता रहा है। कंपनी के एक कर्मचारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि उन्हें मार्च महीने का वेतन 2,000 से 3,000 रुपये कम मिला है। एक अन्य कर्मचारी ने कहा कि उसके हाथ में 40,000 रुपये आते हैं, लेकिन लगभग 70 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ कर्मचारियों के वेतन दो किस्तों में दिए जाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि वेतन की पहले किस्त का भुगतान 31 मार्च को किया गया और दूसरे हिस्से का भुगतान बाद में किया जाएगा।

एक दूसरी विमानन कंपनी गो एयर ने बिना वेतन अवकाश की बात कही है और कहा है कि वेतन का भुगतान दो हिस्सों में किया जाएगा। इस बीच, क्षेत्रीय विमानन कंपनी डक्कन एयर ने रविवार को कहा कि वह अपना परिचालन चार महीनों के लिए बंद कर रही है और इस दौरान कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

सीएलसी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार सद्भाव पूर्ण माहौल में इस समस्या का समाधान निकालना चाहती है और नियोक्ताओं के खिलाफ के खिलाफ कानूनी नहीं करना चाहती है। अधिकारी ने कहा कि इस समय सभी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हम चाहें तो कानूनी कदम उठा सकते हैं, लेकिन यह एक अच्छा विकल्प नहीं माना जाएगा। हम मौजूदा समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं।

स्पासइसजेट अकेली ऐसी कंपनी नहीं है, जहां सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत पडी है। असम में इंडियन ऑयन कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने भी वेतन काटे जाने की शिकातय की है।

श्रम आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों ने दूसरी कंपनियों को भी वेतन नहीं काटने की सलाह दी है। वोडाफोन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जेके सीमेंट, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन और केयर्न इंडिया सहित कुछ कंपनियों ने लॉकडाउन के दौरान वेतन नहीं काटने का आश्वासन दिया है।

एयर डेक्कन ने बंद किया परिचालन

अनीश फडणीस
मुंबई, 5 अप्रैल

एयर डेक्कन ने परिचालन बंद कर दिया है और अपने सभी कर्मचारियों को बिना वेतन के विश्रामकालीन अवकाश दे दिया है। देश की सबसे पहली किफायती विमानन सेवा कंपनी एयर डेक्कन ने क्षेत्रीय सेवा देने वाले ऑपरेटर के तौर पर साल 2017 में अपनी सेवाएं बहाल की थी। एक साल बाद जीएसईसी मोनार्क ने इस विमानन कंपनी की 50 फीसदी हिस्सेदारी ली और कंपनी ने गुजरात में तीन गंतव्यों के लिए अपनी सेवाएं दी। अभी कंपनी के बेड़े में सिर्फ बीचक्राफ्ट 1900 डी विमान है।

कंपनी के सीईओ अरुण कुमार सिंह ने आज कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा है, हालिया वैश्विक व देसी मसलों और भारतीय नियामक की तरफ से जारी निर्देशों को देखते हुए एयर डेक्कन के पास अगले आदेश तक परिचालन बंद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जीएसईसी एविएशन के निदेशक शैशव शाह ने कहा कि विमानन कंपनी अपना परिचालन बंद करने के लिए बाध्य हुई।

लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव दिखेगा: सर्वेक्षण

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 5 अप्रैल

कोरोनावायरस (कोविड-19) के फैलने और उसकी रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का घरेलू अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव दिखेगा। अधिकतर कंपनियों ने आशंका जताई है कि चालू और पिछली तिमाही में उनके राजस्व और मुनाफे में उल्लेखनीय गिरावट आ सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा किए गए सीईओ स्नैप पोल से यह खुलासा हुआ है। सर्वेक्षण में लॉकडाउन के कारण मांग में गिरावट और रोजगार प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए इस सर्वेक्षण में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के करीब 200 सीईओ ने भाग लिया। सर्वेक्षण में शामिल अधिकतर सीईओ ने आशंका जताई कि चालू तिमाही (अप्रैल से जून 2020) और पिछली तिमाही (जनवरी से मार्च 2020) के लिए राजस्व में 10 फीसदी से अधिक और मुनाफे में 5 फीसदी से अधिक की गिरावट दिख सकती है। घरेलू कंपनियों के राजस्व और मुनाफे में इस भारी गिरावट से जीडीपी वृद्धि पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है।

इसके अलावा अधिकतर कंपनियों (80 फीसदी) कंपनियों ने दावा किया कि उनकी इन्वेंटरी फिलहाल बेकार पड़ी है। हालांकि 40 फीसदी से अधिक कंपनियों ने उम्मीद जताई कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद उनका स्टॉक एक महीने से अधिक समय तक चलेगा। इससे पता चलता है कि लॉकडाउन अवधि के बाद कंपनियों को मांग में कमी बने रहने के आसार दिख रहे हैं।

लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं उत्पादों के उत्पादन एवं आपूर्ति करने वाली अधिकतर कंपनियों को आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में व्यवधान से जूझना पड़ रहा है। कंपनियों ने कहा कि श्रमिकों का अभाव और उत्पादों की आवाजाही में व्यवधान एक प्रमुख समस्या बनकर उभरी है। चाहे आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण हो अथवा गोदाम में भंडारण एवं परिवहन अथवा खुदरा बिक्री, हर मोर्चे पर ऐसी समस्याएं दिख रही हैं। हालांकि सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण, परिवहन एवं वितरण की अनुमति दी है लेकिन स्थानीय स्तर पर आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर भी लॉकडाउन का असर दिख रहा है।

रोजगार के मोर्चे पर करीब 52 फीसदी कंपनियों को कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण अपने संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नुकसान की आशंका दिख रही है। सीआईआई ने कहा कि जिस अनुपात में छंटनी की आशंका जताई जा रही है वह काफी चौंकाने वाली है। करीब 47 फीसदी कंपनियों ने कहा कि करीब 15 फीसदी छंटनी होने के आसार हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि 32 फीसदी कंपनियों ने उम्मीद जताई कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 15 से 30 फीसदी के दायरे में छंटनी हो सकती है।

- कोविड-19 लॉकडाउन के प्रभाव पर सीआईआई का सीईओ सर्वेक्षण
- सर्वेक्षण में शामिल 52 फीसदी सीईओ ने जताई रोजगार के नुकसान की आशंका
- सर्वेक्षण के अनुसार, राजस्व में दिख सकती है 10 फीसदी से अधिक की गिरावट
- सर्वेक्षण में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के करीब 200 सीईओ ने भाग लिया
- करीब 47 फीसदी कंपनियों ने कहा कि करीब 15 फीसदी छंटनी होने के आसार

निवेशकों को निवेश दोगुना करने की जरूरत

कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक व्यवधान से स्टार्टअप जगत को भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्फोसिस के सह-संस्थापक और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की स्टार्टअप समिति के चेयरमैन **क्रिस गोपालकृष्णन** ने **नेहा अलावधी** से बातचीत में कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए उद्योग संगठन सरकार से स्टार्टअप के लिए आसान नियामकीय अनुपालन और कर रियायत की मांग कर रहा है ताकि उसे अपना कारोबार बरकरार रखने में मदद मिल सके। पेश हैं मुख्य अंश:

मौजूदा परिदृश्य (कोविड-19 के संदर्भ में) स्टार्टअप, विशेष कर छोटे स्टार्टअप के लिए कैसा दिख रहा है?
यह स्टार्टअप के लिए बहुत कठिन अवधि है, चाहे वे छोटे हों या बड़े। कुछ स्टार्टअप ने 2008 अथवा 2011 में कठिन परिस्थिति देखी है लेकिन अधिकतर के लिए ऐसा पहली बार हो रहा है। इसलिए उनके लिए यह जीवन में पहली बार दिखने वाला प्रभाव है। उनके लिए मेरी सलाह यह है कि अपने कर्मचारियों के साथ जुड़े रहें, घर से काम करें और पता लगाएं कि आप अपने कारोबार को कैसे जारी रख सकेंगे। दूसरा, नकदी बचाकर रखें। अपने सभी खर्च पर गौर करें और जहां संभव दिखे वहां खर्च में कटौती करें।

कुछ स्टार्टअप भी वेतन में कटौती पर विचार कर रहे हैं, खासकर वरिष्ठ स्तर पर। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि वे अपने निवेशकों के पास जाएं और पता लगाएं कि वे कितनी मदद कर सकते हैं अथवा निवेश बढ़ा सकते हैं या नहीं। निवेशक भी अपने निवेश की सुरक्षा के लिए उसी रणनीति पर चल रहे हैं। निवेश के लिए किसी नई कंपनी पर विचार करने के बजाय उन्हें अपने मौजूदा निवेश को दोगुना करने की आवश्यकता है ताकि वे दूसरी तरफ बेहतर स्थिति में आ सकें अथवा कम से कम अपना अस्तित्व बचा सकें। अच्छी बात यह है कि इस संकट से निपटने के लिए पूरा समुदाय साथ आया है और वे नि:शुल्क आधार पर परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।

क्या आपने स्टार्टअप की मदद के लिए सीआईआई के स्तर पर सरकार से सिफारिश की है?
हम कुछ दिनों के लिए मोहलत, कर में रियायत और नियामकीय अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को फिलहाल स्थगित करने के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा एक खास स्तर से नीचे के वेतन के लिए मदद जैसी बातें भी हो सकती हैं ताकि कंपनियों को छंटनी न करना पड़े। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एमएसएमई क्षेत्र ने अनुरोध किया है। यह अतिआवश्यक है क्योंकि स्टार्टअप को लेकर उम्मीदें कहीं अधिक हैं। उन्होंने एक नया कारोबार खड़ा किया है और हमें उसे खोना नहीं चाहिए। यदि मौजूदा परिदृश्य में कई स्टार्टअप को बंद होना पड़ता है तो नया कारोबार शुरू करने की चाहत रखने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो जाएगी।

सुधार के बारे में स्टार्टअप क्या सोचते हैं? कब तक सुधार होने की उम्मीद है?
मैं समझता हूं कि सुधार दो चरणों में होगा- पहला, आप इस वैश्विक महामारी के कारण सामाजिक दूरी के बीच अपना कारोबार किस प्रकार करते हैं। लॉकडाउन 15 अप्रैल को हटाया जा सकता है लेकिन वायरस तब भी मौजूद रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि लोगों को काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण कैसे उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, इस स्वास्थ्य आपातकाल के बाद की स्थिति होगी जहां हम पूरी तरह आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

क्या निवेश चक्र को तेजी पकड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा?
हां, ऐसा हो सकता है। हमने निवेशकों से अनुरोध किया है और वे स्थिति पर नजर रख रहे हैं। कई निवेशक तो अपने निवेश को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। अभी जो स्थिति दिख रही है, उससे कुछ कंपनियां विफल हो सकती हैं। इसलिए हमें उन सब का ध्यान रखना होगा।

स्टार्टअप के लिए सरकार की ओर से क्या नीतिगत मदद की गई है? क्या उसमें सामान्य तौर पर नीतिगत पंगुता तो नहीं दिख रही?
मैं इसे नीतिगत पंगुता नहीं कहूंगा। हमें सरकार से काफी समर्थन मिला है। गुरुवार को भी केंद्रीय वाणिज्यि एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ्थ एक बैठक हुई थी। इसलिए हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार का रुख काफी मददगार है और वह इस क्षेत्र की मदद करना चाहती है। उन्होंने यह भी महसूस किया है कि उद्योग के एक भाग के रूप में इसे बरकरार रहने की जरूरत है क्योंकि इसमें लोग काफी जुनून के साथ काम करते हैं।

लॉकडाउन के बाद छोटी कारों की बढ़ेगी बिक्री!

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 5 अप्रैल

वाहन विनिर्माताओं को आगे कहीं अधिक चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। भारत में आर्थिक नरमी और कमजोर ग्राहक धारणा के कारण वाहनों की बिक्री रफ्तार पहले से ही सुस्त है और मार्च में इसे जबरदस्त झटका लगा। महीने के दौरान शीर्ष वाहन कंपनियों की बिक्री में एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 64 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि कोरोनावायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के बीच उम्मीद की एक किरण भी दिख रही है। लॉकडाउन की इस 21 दिनों की अवधि खत्म होने के बाद संभवत: चरणबद्ध तरीके से इसे हटाया जा सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे में जो लोग कार खरीदने पर विचार कर रहे थे, वे वास्तव में खरीदारी करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

विश्लेषकों ने कहा कि सामाजिक दूरी संबंधी मानदंडों और स्वच्छता को लेकर बढ़ती जागरूकता के कारण दैनिक यात्र करने वाले लोग सार्वजनिक परिवहन अथवा ओला, उबर जैसी साझा मोबिलिटी सेवाओं के इस्तेमाल से बचेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद लोग मेट्रो, लोकल ट्रेन अथवा बस जैसी भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक परिवहन सेवा का इस्तेमाल करने के बजाय अपनी कार में यात्रा करना पसंद करेंगे। इस प्रवृत्ति से प्रवेश स्तर की कारों अथवा 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारों की बिक्री में तेजी दिख सकती है। डेलॉयट के प्रमुख (वाहन क्षेत्र) राजीव प्रताप सिंह ने कहा, 'हालांकि फिलहाल तस्वीर स्पष्ट नहीं है लेकिन उम्मीद की किरण दिख रही है। विशेष तौर पर प्रवेश स्तर की कारों की मांग में तेजी दिख सकती है। यह इस श्रेणी में मौजूद सभी वाहन विनिर्माताओं के लिए एक अवसर है और उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए।'

सिंह ने कहा कि जिन लोगों के पास कार नहीं है वे पहले से ही कार खरीदने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। इससे पुरानी कारों की बिक्री में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा, 'साझा परिवहन सेवा के इस्तेमाल में जोखिम कहीं अधिक है और इस प्रकार की सेवाओं अथवा साझा मोबिलिटी प्लेटफॉर्म की मांग में जबरदस्त गिरावट दिखेगी।'

कार्नी के प्रमुख (ऑटोमोटिव) राहुल मिश्रा ने भी इससे सहमति जताई। उन्होंने कहा, 'हम जिस सामाजिक दूरी पर अमल कर रहे हैं वह बुनियादी तौर पर तमाम पारंपरिक तरीकों को बदलने वाली है। ऐसी एक प्रवृत्ति के तहत सार्वजनिक अथवा साझा परिवहन सेवा के बजाय निजी वाहनों के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जाएगी।'

मिलेनियल्स भी अब कार खरीदने के बारे में सोच सकते हैं जबकि इससे पहले वे कार खरीदने के बजाय ओला अथवा उबर जैसी सेवाओं के इस्तेमाल को प्राथमिकता देते थे। उनकी पसंद भी छोटी और कॉम्पैक्ट कार हो सकती है। मौजूदा संकट से जूझ रहे वाहन विनिर्माताओं को किसी भी पूर्वानुमान के प्रति काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है।

कार बाजार की अग्रणी कंपनी मारुति सुजूकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा, 'हमें यह देखना होगा कि लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद मांग कैसे बढ़ेगी। पहले ऐसा कोई अनुभव न होने कारण कुछ भी कहना महज अटकलबाजी होगी।'यात्री वाहन बनाने वाली एक अन्य कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, 'मौजूदा स्थिति में फिलहाल कुछ भी अनुमान जाहिर करना जल्दबाजी होगी। हम अपने चैनल साझेदार एवं वेंडर साझेदारों की मदद करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मौजूदा परिस्थिति में औसत वेतनभोगियों की पहली प्राथमिकता कार खरीदने की होगी।'

तेल कंपनियों की बढ़ी चिंता

अमृता पिल्लई
मुंबई, 5 अप्रैल

तेल विनणन कंपनियों (ओएमसी) ने विपणन श्रेणी में पेट्रोलियम उत्पाद कीमतों को अब तक बरकरार रखा है। इससे कंपनियों को कच्चे तेल की कीमतों में किसी भी तेजी से निपटने में काफी मदद मिलेगी। पिछले एक पखवाड़े के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को लेकर अनिश्चितता के कारण तेल विपणन कंपनियों की चिंता बढ़ गई है।

एसऐंडपी प्लैट्स ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा, 'तेल उत्पादन में कटौती के मुद्दे पर सऊदी अरब द्वारा ओपेस गठबंधन एवं अन्य उत्पादकों की आपात बैठक बुलाए जाने के बाद गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतों में 25 फीसदी की तेजी आई। एनवाईएमईएक्स फ्रंट मंथ क्रूड 5.01 डॉलर बढ़त के साथ 25.32 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ।'

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कच्चे तेल में 1 से 1.5 करोड़ बैरल प्रति दिन कटौती के समझौते का संकेत दिया था। परामर्श फर्म डेलॉयट टच तोमात्सु के पार्टनर देवाशिष मिश्रा ने कहा, 'ट्रंप के ट्वीट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गुरुवार को आई अचानक तेजी के बावजूद तेल कीमतों में फिलहाल नरमी रहने के आसार हैं जो तेल विपणन कंपनियों के लिए अच्छा रहेगा।'

- तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव, मांग में अनिश्चितता से ओएमसी को झटका
- उत्पादन में कटौती से कच्चे तेल कीमतों में गिरावट थम सकती है लेकिन इससे मांग-आपूर्ति में नहीं होगा संतुलन

कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही गिरावट थमेगी लेकिन इसे मांग-आपूर्ति में संतुलन स्थापित नहीं होगा।

एक घरेलू ब्रोकरेज फर्म के विश्लेषक ने कहा, 'मांग में तेजी से गिरावट दिख रही है।' तेल विपणन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसी तरह की चिंता जताई। अब तक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) अपनी रिफाइनरी में उत्पादन 30 फीसदी तक घटा चुकी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) ने उत्पादन में 20 फीसदी की कटौती की है। इन दोनों कंपनियों ने घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में गिरावट के मद्देनजर यह पहल की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यदि देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 15 अप्रैल से आगे बढ़ाई गई तो रिफाइनरियों को उत्पादन में कहीं अधिक कटौती करने की जरूरत होगी। एक सरकारी तेल कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'तेल विपणन कंपनियां कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव का उपयोग कर रही हैं। एक दिन की तेजी अथवा गिरावट से हमें कोई चिंता नहीं है। यदि कीमत स्थिर रहती है तो हमें इन्वेंटरी के फायदे या नुकसान की चिंता होती है। अब तक डीजल का मार्जिन अन्य उत्पादों के मुकाबले बेहतर दिख रहा है। साथ ही कीमत लगातार ऊंची रहने से कार्यशील पूंजी भी प्रभावित होती है।'

विश्लेषकों ने मार्च तिमाही के लिए भारी इन्वेंटरी नुकसान का पहले ही आकलन किया है।

रोजगार पेशकश वापस लेने लगीं फर्में

अमेरिकी कंपनी गार्टनर ने वापस ली नौकरी, कुछ ने इंटर्नशिप पर लगाई रोक

अभिषेक रक्षित, समरीन अहमद, गिरीश बाबू, विनय उमरजी और अर्णव दत्ता
कोलकाता/बेंगलुरू/चेन्नई/अहमदाबाद /नई दिल्ली, 5 अप्रैल

कोविड-19 महामारी की बढ़ती आशंका के बीच विभिन्न देश पूरी तरह ठप पड़ गए हैं। ऐसे में नियोक्ता, खासकर बहुराष्ट्रीय नियोक्ता अपनी रोजगार नीति पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं। इसके चलते देश के शीर्ष प्रतिष्ठानों की प्लेसमेंट प्रक्रिया उलझ गई है।

अमेरिकी शोध और सलाहकार फर्म गार्टनर ने भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) के युवाओं को की गई तमाम रोजगार पेशकश रद्द कर दी हैं। आईआईएम के कोलकाता और अहमदाबाद परिसर ने इसकी पुष्टि की है। आईआईएम कोलकाता के प्लेसमेंट से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि गार्टनर ने रोजगार के अलावा इंटर्नशिप पर भी रोक लगा दी है। आईआईएम-अहमदाबाद के प्लेसमेंट प्रमुख अमित कर्ण ने भी कहा कि गार्टनर ने रोजगार पेशकश खत्म कर दी है। कंपनी ने तीन छात्रों को नियुक्ति दी थी। उन्होंने कहा कि संस्थान प्रभावित छात्रों के लिए नए अवसर तलाश रहा है। गार्टनर ने कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। अन्य किसी कंपनी ने अब तक ऐसा नहीं किया है।

आईआईएम-बेंगलूरु के एक छात्र ने लिंक्डइन पर रोजगार अवसर छिनने की जानकारी दी। हालांकि उसके संस्थान का कहना है कि वह कंपनी से संपर्क में है और प्रभावित छात्रों को दूसरे अवसर दिलाने के लिए प्रयासरत है। आईआईएम बेंगलूरु की करियर विकास सेवा के प्रमुख यू दिनेश कुमार ने कहा, 'सभी कंपनियों ने कहा है कि वे अपनी बात पर कायम हैं। पेशकश को केवल टाला गया है। 15 अप्रैल के बाद लॉकडाउन को लेकर स्थिति सामान्य होने के बाद वे योजनाओं पर काम करेंगी। वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों ने भी पेशकश टाली है क्योंकि उनके लिए फिलहाल इंटर्नशिप शुरू करना मुश्किल है।' कुमार ने कहा कि खाड़ी कुछ कंपनियों ने प्लेसमेंट पेशकश समाप्त की है क्योंकि यात्राओं पर प्रतिबंध लगा है। लेकिन इन छात्रों के लिए नए अवसर तलाशे जा रहे हैं।

एक प्रमुख एफएमसीजी कंपनी ने इंटर्नशिप के लिए वर्चुअल असाइनमेंट का रास्ता चुना है। कंपनी ने नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय लॉकडाउन समाप्त होने के बाद लेगी।

आईआईएम-कोलकाता में एक स्टार्टअप ने भी इंटर्नशिप की पेशकश समाप्त की है। वहां के अधिकारी ने बताया, 'कुछ नियमित नियोक्ता अतिरिक्त इंटर्न को चुन रहे हैं। प्लेसमेंट टीम गंवाए अवसरों की पूर्ति करने का प्रयास कर रही है।'

आईआईटी मद्रास अपने छात्रों को ऑनलाइन क्लास देने की तैयारी कर रहा है

आईआईएम-शिलॉन्ग की प्लेसमेंट समिति के एक अधिकारी ने कहा कि पूर्णकालिक अवसर तो बरकरार हैं लेकिन मध्यम अवधि के संस्थानों और स्टार्ट अप ने समर इंटर्नशिप समाप्त की है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी ऐसी स्थितियों से जूझ रहे हैं। ऑल आईआईटीज प्लेसमेंट कमेटी ने नियोक्ताओं से रोजगार रद्द न करने का आग्रह किया है। अब तक दिल्ली, कानपुर और मद्रास आईआईटी में कम से कम एक नियोक्ता ने हाथ खींच लिए हैं। आईआईटी-मद्रास के प्लेसमेंट सलाहकार सीएस शंकर राम ने कहा, 'एक कंपनी ने कहा कि वह नियुक्तियां नहीं दे सकती। अन्य कंपनियों ने ऐसा कुछ नहीं कहा है इसलिए हम आशान्वित हैं। प्रभावित छात्रों के लिए दूसरे अवसर तलाशे जाएंगे।'

आईआईटी के निदेशकों ने कंपनियों से अपील की है कि वे ऐसा न करें। आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी रामगोपाल राव ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा, 'इस समय अगर कोई रोजगार या इंटर्नशिप अवसर छिना तो छात्र ऐसी अन्य नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।'

अन्य संस्थानों से सक्रियता बढ़ा दी है। आईआईटी रुड़की के प्लेसमेंट प्रभारी प्रोफेसर विनय शर्मा ने कहा कि वहां अब तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है और उनका संस्थान कंपनियों के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा है। आईआईटी गांधी नगर के करियर विकास सेवा प्रमुख अभय राज सिंह गौतम ने कहा कि उनके संस्थान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वह लगातार नियोक्ताओं के साथ संपर्क में है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो संस्थान उचित कदम उठाएगा।

प्रभावित छात्र भी सोशल मीडिया के माध्यम से संभावित नियोक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। आईआईएम-बेंगलूरु के एक छात्र ने उत्पाद प्रबंधन, रणनीति, परामर्श अथवा एनालिटिक्स में अवसर तलाशने शुरू कर दिए हैं।

आईआईटी-मद्रास के शंकर राम ने कहा, हम अपने छात्रों को ऑनलाइन क्लास देने की तैयारी कर रहे हैं। उन छात्रों को प्राथमिकता दी जा रही है जो स्नातक कर रहे हैं ताकि वे ज्यादा प्रभावित न हों। नियुक्ति की तिथियां प्राय: जून से आरंभ होती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र उसके लिए पूरी तरह तैयार रहें। 15 अप्रैल को संस्थान खुलने के बाद हम बेहतर आकलन कर सकेंगे।' वह मानकर चल रहे हैं कि नियोक्ता अपनी पेशकश का मान रखेंगे।

संकट के बाद की रणनीति में जुटी कंपनियां

पृष्ठ-1 का शेष

दूसरे शब्दों में कहें तो श्रमिकों के अचानक पलायन और सोशल डिस्टेंसिंग की हालत में हमें चुनौतियों से निपटने में स्वचालन काफी मदद करेगा। स्थानीयकरण से लागत में कमी आएगी। इस तरह, हरेक को संतुलन स्थापित करने की दिषा में काम करना होगा।'कुछ कंपनियां अपने कार्यालयों का आकार छोटा करने पर विचार कर रही हैं क्योंकि घर से काम करने का प्रयोग सफल साबित हुआ है। वाहन, वित्तीय क्षेत्र, आतिथ्य, रक्षा एवं आईटी क्षेत्रों में उपस्थिति रखने वाली मुंबई स्थित एक बड़े समूह के चेयरमैन ने अपने कारोबार मुख्य कार्याधिकारियों से जानना चाहा है कि क्या वे विपणन एवं बिक्री विभागों के कर्मचारियों को एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आने के लिए कह सकते हैं और किराया लागत कम कर सकते हैं।

सेवा क्षेत्र की कंपनियां अपनी कार्य प्रणाली अधिक सुरक्षित बनाने की दिषा में काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल ऐप्लीकेशन आधारित यात्रा सेवा देने वाली कंपनी उबर इंडिया के लिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद यात्रियों और चालकों के मन से संक्रमण का भय दूर करना सबसे बडी चुनौती है। कंपनी इसके लिए यात्री कार को अधिक सुरक्षित बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए कार की छत से लेकर फर्श तक प्लास्टिक की परत लगाना और चालकों के लिए सैनिटाइजर और मास्क आदि अनिवार्य किए जाने पर विचार हो रहा है। भारत व दक्षिण एशिया में उबर के अध्यक्ष प्रदीप परमेश्वरन कहते हैं, 'हम स्वास्थ्य कर्मियों के इस्तेमाल में लगे 150 वाहनों में ऐसे प्रयोग करना चाहते हैं। लॉकडाउन के बाद यह संख्या बढाकर 2 लाख तक करने की तैयारियों में जुटे हैं।' कोविड-19 संकट खत्म होने के बाद कर्मचारियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ बदलाव होंगे।

नेस्ले इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबध निदेशक सुरेश नारायण कहते हैं, 'घर से लगातार काम करने से कर्मचारियों में तनाव एवं चिंता का स्तर खासा बढ़ गया है। इनसे निपटने के लिए कंपनी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य पहल आदि शुरू किए हैं। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे।'कोविड-19 संकट के बाद मंदी या आर्थिक सुस्ती से निपटना कंपनियों के लिए तत्काल सबसे बड़ी चुनौती है। विभिन्न कंपनियों का षीर्ष प्रबंधन इस मोर्चे पर पहले ही जुट गया है और वे फिलहाल अपने पास नकदी भंडार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।

थॉमस कुक इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक माधवन मेनन कहते हैं, 'हमारे बही-खाते में बड़ी मात्रा में नकदी है और हम सभी नकदी स्रोतों और देनदारियों की समीक्षा कर रहे हैं। अधिक से अधिक नकदी रखने के लिए सभी गैर-आवश्यक खर्च रोक दिए गए हैं।'(साथ में अनीश फडनीश, अर्णव दत्ता और सुदीप्तो डे)

एक और पैकेज पर विचार

सरकार ने लॉकडाउन समाप्त होने के बाद की संभावित स्थिति पर विचार करना शुरू कर दिया है। कोरोनावायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार एक और राहत पैकेज पर विचार कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। हालांकि इस दिशा में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। यदि सरकार की तरफ से किसी पैकेज की घोषणा होती है तो यह सरकार की तरफ से कोरोनावायरस को फैलने से रोकने की दिशा में तीसरी अहम पहल होगी। *भाषा*

उतारचढ़ाव से पीएनबी एचएफसी की इक्विटी योजना पर असर : इक्रा

अभिजित लेले
मुंबई, 5 अप्रैल

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पूंजी बाजार में मचे हाहाकार से पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड की 1,700 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना के सामने चुनौती खड़ी हो गई है।

साथ ही पूंजी जुटाने में देरी से लिवरेज प्रोफाइल में सुधार की संभावना खत्म हो जाएगी और आपात स्थिति के लिए उपलब्ध सहजता सीमित हो जाएगी। यह मानना है रेटिंग एजेंसी इक्रा का।

रेटिंग एजेंसी ने एचएफसी के गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र और टियर-1 बॉन्डों की रेटिंग डाउनग्रेड कर एए प्लस से एए कर दी है क्योंकि उसकी परिसंपत्ति गुणवत्ता कमजोर हो रही है, खास तौर से थोक लोन पोर्टफोलियो में।

रेटिंग में संशोधन पूंजी जुटाने के कार्यक्रम में देरी और नियोजित इक्विटी से कम निवेश को देखते हुए किया गया है। पीएनबी एचएफसी ने हाल में 1,700 करोड़ रुपये इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी ली है, जिसके बारे में इक्रा का कहना है कि यह रकम पहले प्राकल्पिक रकम से कम है।

■ एचएफसी की योजना 1,700 करोड़ रुपये जुटाने की है लेकिन और रकम की होगी दरकार

■ इक्रा ने ऋणपत्र, टियर-1 बॉन्डों को किया डाउनग्रेड

इसके अलावा प्रोफाइल पर संकेंद्रित जोखिम और चुनौतीपूर्ण माहौल को देखते हुए कंपनी की पूंजी की दरकार बढ़ गई है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 4.97 फीसदी की गिरावट के साथ 161.6 रुपये पर बंद हुआ।

कंपनी की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां दिसंबर 2019 के आखिर में 86,297 करोड़ रुपये की थी। सार्वजनिक बैंक पीएनबी और कार्लाइल समूह के पास इस कंपनी की क्रमश: 32.65 फीसदी और 32.22 फीसदी हिस्सेदारी थी। ये आंकड़े 31 दिसंबर 2019 के हैं।

बाजार के हालात को देखते हुए कंपनी ने पोर्टफोलियो में नरमी देखी है और यह निकट भविष्य में बना रह सकता है।

कंपनी का जोखिम अच्छे कोलेटरल यानी जमानत के कारण कम हुआ है, साथ ही कंपनी की जोखिम प्रबंधन की व्यवस्था और प्रक्रिया भी बेहतर है। लिवरेज स्तर में कमी भी कंपनी के लिए लाभकारी है। कंपनी होम लोन, संपत्ति के बदले कर्ज, बिल्डर लोन और लीज रेंटल डिस्काउंटिंग की पेशकश करती है।

एचडीएफसी बैंक की उधारी में 21 फीसदी की उछाल

सुब्रत पांडा
मुंबई, 5 अप्रैल

निजी क्षेत्र के देश के सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि उसकी उधारी मार्च तिमाही के आखिर में 21 फीसदी बढ़ी जबकि जमा आधार में इस दौरान 24 फीसदी की उछाल आई। बैंक की उधारी वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में 9.93 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 8.94 लाख करोड़ रुपये थी। यह ऐसे समय में देखने को मिला है जब कुल मिलाकर बैंक की उधारी की रफ्तार कमजोर रही है क्योंकि आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण है।

इसी तरह निजी बैंक की जमाओं का आधार चौथी तिमाही में 11.46 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 9.23 लाख करोड़ रुपये रहा था। हाल के समय में निजी बैंकिंग क्षेत्र खास तौर से छोटे बैंकों ने येस बैंक के संकट के बाद जमा आधार में कमी देखी है।

बैंक का चालू व बचत खाते का अनुपात तिमाही में 42 फीसदी रहा, जो मार्च 2019 में 42.4 फीसदी थी और 31 दिसंबर 2019 को 39.5 फीसदी। लेनदार ने तिमाही के दौरान 5,479 करोड़ रुपये का लोन खरीदा, जो एचडीएफसी के साथ होम लोन की व्यवस्था के तहत लिया गया।

गुरुवार को मूडीज ने कहा था कि कोरोनावायरस महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर अवरोध से भारत की अर्थव्यवस्था में नरमी आएगी। बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर भी असर होगा, जो कॉरपोरेट, एसएमई व खुदरा क्षेत्रों में है, जिससे बैंक के लाभ व पूंजी पर दबाव पड़ेगा।

स्टार्टअप को वित्त जुटाने में होगी मुश्किल

साई ईश्वर और पीरजादा अबरार
मुंबई/बेंगलूरु, 5 अप्रैल

कोरोनावायरस तथा इसके बाद लॉकडाउन के चलते देश के स्टार्टअप पारितंत्र को गंभीर झटका लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक बार स्थिति ठीक होने के बाद भी शुरुआती दौर के अधिकांश स्टार्टअप को वित्त जुटाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूंजी निवेशक नए विचारों में अपनी पूंजी लगाने के बजाए पहले से वित्त पोषित कंपनियों में ही निवेश करना बेहतर समझेंगे।

वेंचर कैपिटल फर्म लाइटबॉक्स में पार्टनर प्रशांत मेहता ने कहा, 'क्या भारत में स्थिति बेहतर हो रही है, क्या यह स्थिर हो रही है या खराब? पूंजी निवेशक धन निवेशक करने के लि उचित समय को तलाशेंगे। हालांकि अगर स्थिति खराब हुई तो कम से कम शुरुआती स्तर के स्टार्टअप के लिए पैसा जुटाने में समय लगेगा।' उन्होंने कहा, 'हालांकि मजबूत विचारों तथा एक सिस्टम के साथ आने वाले मजबूत स्टार्टअप को पैसे जुटाने में परेशानी नहीं होगी।'

यह भारत में शुरुआती स्तर की फंडिंग के तौर पर आता है और जनवरी-मार्च तिमाही में यह राशि पिछली पांच तिमाहियों में सबसे कम रही। वेंचर इंटेलिजेंस द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, बीते साल की समान अवधि की तुलना में इस तिमाही में शुरुआती स्तर की फंडिंग 28 प्रतिशत घटकर 4.8 करोड़ डॉलर रह गई। इस दौरान हुए सौदों की संख्या भी एक साल पहले के 70 सौदों से घटकर 40 रह गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक अनिश्चितता के चलते अधिकांश निवेशक पहले से वित्त पोषित कंपनियों में ही निवेश करने को वरीयता देंगे

बेंगलूरु स्थित पूंजी निवेश फर्म 'स्पेशल इनवेस्ट' के सह-संस्थापक विशेश राजाराम के अनुसार, ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि शुरुआती स्तर पर होने वाली फंडिंग का ग्राफ बहुत जल्दी गिर जाएगा हालांकि वापसी करने वालों में भी ये सबसे आगे होंगे। वह कहते हैं, 'हमारी बहुत सारी (पोर्टफोलियो) कंपनियां अगले 6-9 महीनों के लिए राजस्व में कमी को नहीं देख रहीं और अगले 18-24 महीनों के लिए अपने रोडमैप को पेश कर रही हैं।'

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले पूंजी निवेशक अगले एक से तीन महीनों में स्थिति को काफी बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। स्वतंत्र सलाहकार और कलारी कैपिटल में वेंचर पार्टनर रहे श्रीधर प्रसाद ने कहा, 'निवेश फर्मों को किसी अनजाने क्षेत्र में नया निवेश करने के बजाय अपने मौजूदा निवेश को बचाने तथा अगली तिमाहियों में उनके बेहतर प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।'

वेंचर इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार, इस साल मार्च तिमाही में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले कुल उद्यम पूंजी निवेश काफी कम रहा है। इस दौरान उद्यम पूंजी निवेश 22 प्रतिशत घट गया।

केयर्न ने भी अनुबंध में बदलाव चाहा, समयसीमा विस्तार की मांग

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 5 अप्रैल

कोरोनावायरस का प्रसार रोकने के उद्देश्य से देश भर में चल रहे लॉकडाउन ने केयर्न ऑयल ऐंड गैस की योजनाओं को प्रभावित किया है और निजी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी कही जाने वाली केयर्न ने फोर्स मेजर लागू करने के लिए सरकार से संपर्क साधा है। कंपनी ने खुली लाइसेंस नीति (ओएएलपी) के तहत आवंटित सौदों के लिए समयसीमा विस्तार की मांग की है।

केयर्न को ओएएलपी के पहले दौर की बोली में 41 ब्लॉक और दूसरे तथा तीसरे दौर की बोली में पांच-पांच ब्लॉक मिले थे। साथ ही डीएसएफ नीति के तहत भी कंपनी को दो क्षेत्र आवंटित हुए थे। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात में फैले हैं। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि वेदांत की इस इकाई के अलावा भी ओएएलपी तथा डीएसएफ दौर के तहत क्षेत्र आवंटन पाने वाली कई कंपनियों ने फोर्स मेजर लागू कर दिए हैं।

इस विषय से जुड़े एक सरकारी सूत्र ने कहा, 'केयर्न ने ओएएलपी की समयसीमा में विस्तार की मांग की है क्योंकि हालिया लॉकडाउन के चलते भूकंप संबंधी कई सर्वे तथा संबंधित गतिविधियां रूकी हुई हैं। लॉकडाउन से प्रेटोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (पीईए) जारी करने तथा पर्यावरणीय मंजूरी मिलने में भी देरी हो रही है।'

खोज में समस्या

51 ओएलएपी में केयर्न को मिले कुल ब्लॉक

94 ओएलएपी के चार दौर में दिए गए कुल ब्लॉक

11 ओएएलपी के तहत पेश किए गए ब्लॉक छह राज्यों में फैले हुए हैं

136,790 वर्ग किमी
ओएएलपी-4 के तहत दिए गए कुल क्षेत्र

ओएएलपी : ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी

दिसंबर के बाद से कई कंपनियों के काम रूके हुए थे क्योंकि दूसरे देशों में कोविड-19 के प्रसार के चलते भूकंपीय उपकरण चीन तथा दूसरे देशों में फंस गए थे। केयर्न को कुछ ब्लॉकों के लिए खनन पट्टा मिला, जबकि असम, गुजरात और कुछ अपतटीय क्षेत्रों के कुछ ब्लॉकों में भूकंपीय सर्वेक्षण शुरू किए गए थे।

सूत्रों का कहना है कि जिन दूसरी कंपनियों ने फोर्स मेजर लागू किया है, उनमें मुंबई स्थि ऑयलमैक्स एनर्जी और दुबई स्थित दक्षिण एशियाई सलाहकार फर्म एफजेडई शामिल हैं। ये कंपनियां अंवेषण चरण के तहत विभिन्न प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समयसीमा का विस्तार चाहती हैं।

उद्योग से जुड़े एक सूत्र ने कहा, 'भूकंपीय कार्यों में देरी का मतलब है संभावना पहचान, ड्रिलिंग, और मूल्यांकन भी देरी होना। कोरोनावायरस और कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की गिरती कीमतें अन्वेषण एवं उत्पादन व्यवसाय को अलाभकारी बना रही हैं।'

ओएएलपी बोली के दौर में 1,36,790 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले कुल 94 ब्लॉकों को तेल खनन तथा उत्पादन कंपनियों को आवंटित किया गया था। इन ब्लॉकों के ऑपरेटरों ने पेट्रोलियम अंवेषण गतिविधियों की शुरुआत कर दी है या फिर वे पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त करने के अंतिम चरण में हैं।

डीएसएफ के तहत काम करने वाली एकमात्र विदेशी कंपनी साउथ एशिया कंसल्टेंसी के प्रबंध निदेशक डीएस राजपूत कहते हैं, 'हम फोर्स मेजर लागू करने के लिए सरकार से संपर्क कर रहे हैं। यदि समय सीमा बढ़ा दी जाती है, तो हमें लॉकडाउन की क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। लॉकडाउन के बाद भी परिचालन को सामान्य करने के लिए कम से कम एक तिमाही का समय लगेगा।'

कोविड-19 से स्टील निर्माताओं पर बढ़ रहा है दबाव

उज्ज्वल जौहरी
मुंबई, 5 अप्रैल

मार्च के तीसरे हफ्ते तक मजबूत रहने वाला देसी स्टील कीमतों का परिदृश्य अब निराशाजनक नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले प्रीमियम पर रहने वाली देसी स्टील कीमतों पर दबाव पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन से इन्वेंट्री बढ़ रही है। केयर रेटिंग्स ने कहा है कि देसी स्टील निर्माताओं के प्रदर्शन पर वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में प्रतिकूल असर पड़ सकता है, जिसकी वजह कोविड-19 महामारी और 21 दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है।

लॉकडाउन से कुछ दिन पहले मार्च में स्टील की कीमतें करीब 2 फीसदी फिसली थी, वहीं पूर्वी देशों में औसतन कीमतें 6 फीसदी कम हुई थी। इससे देसी कीमतें पूर्वी देशों से आयातित स्टील कीमतों से पहले ही छह फीसदी प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा था और यह जानकारी विश्लेषकों के आंकड़ों से मिली। उसके बाद वैश्विक कीमतें नरम हुई हैं। 3 अपप्रैल को फ्री ऑन बोर्ड चाइना हॉट रोल्ड कॉइल की कीमतें 23 मार्च के मुकाबले लंदन मेटल एक्सचेंज पर 4 फीसदी और गिरी। चूंकि ग्राहक अनुबंध का नवीनीकरण

कर रहे हैं और इस पर मोलभाव कर रहे हैं, ऐसे में यह जल्द ही स्टील कंपनियों के राजस्व में प्रतिबिंबित होगा। यह कीमतों पर हालांकि दबाव डाल राह है, लेकिन लॉकडाउन के कारण मांग पर असर और बढ़ती इन्वेंट्री से देसी स्टील की कीमतों पर और असर देखने को मिल सकता है।

प्रदर्शन पर असर न सिर्फ मांग व बिक्री मूलल्य के कारण पड़ेगा, बल्कि मार्जिन भी प्रभावित होगा। मुनाफा मार्जिन घटने की संभावना है क्क्योंकि इनपुट कीमतें ज्यादा

कोविड-19 के कारण मांग पर असर के अलावा कंपनियों की इनपुट लागत और कीमतों में संभावित गिरावट से मार्जिन होगा प्रभावित

होंगी और स्टील की कीमतें कमजोर। ओडिशा में हुई हालिया नीलामी में आक्रामक बोली से लौह अयस्क की लागत अल्पावधि में ऊंची रहेगी, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। चीन की नरम स्थिति का मतलब यह है कि लौह अयस्क और कोयले की चीनी मांग बढ़नी शुरू होगा, लिहाजा इनपुट कीमतें प्रभावित होंगी। ऐसे में बिक्री मूल्य को झटका लगेगा और मार्जिन पर दबाव गहरा सकता है। चीन में उत्पादन शुरू होने के मतलब वहां से ज्यादा निर्यात भी होगा। चीन ने हाल में निर्यात पर वैट की छूट 9 फीसदी से बढ़ाकर 13 फीसदी की है। इसका मतलब यह भी होगा कि भारतीय निर्यातकों के लिए मौके कम होंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील न सिर्फ एशिया में दबाव का सामना करेगी, बल्कि यूरोप में भी।

इसके अलावा बढ़ती इन्वेंट्री और उच्च इनपुट लागत से स्टील निर्माताओं की कार्यशील पूंजी की जरूरत पर भी असर दिख सकता है।

एमके ग्लोबल के विश्लेषकों ने कहा कि उन्हें स्टील का मार्जिन वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में तेजी से घटने की आशंका है और दूसरी तिमाही तक यही स्तर बना रहेगा क्योंकि मॉनसून आ जाएगा, जो पारंपरिक रूप से नरम अवधि होती है। विश्लेषकों ने टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील ऐंड पावर जैसे शेयरों की लक्षित कीमत में कटौती की है क्योंकि ये शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

एनपीए पर छह महीने की मोहलत!

पृष्ठ-1 का शेष

इसमें मुख्य समस्या यह है कि केंद्रीय बैंक ने सावधि ऋण के भुगतान में तीन महीने की मोहलत दी है लेकिन साथ ही यह शर्त भी रखी है कि इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए खाता नियमित होना चाहिए। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें कमजोर खातों की स्थिति और बदतर होगी। एक सूत्र ने कहा, 'इससे कमजोर खाते भुगतान में चूक कर सकते हैं और मौजूदा नियमों के मुताबिक उन्हें एनपीए घोषित किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि ब्याज भुगतान में कोई छूट नहीं दी गई है। ये खाते ब्याज के भुगतान में सक्षम नहीं हैं क्योंकि जून 2020 तिमाही में बिक्री बहुत कमजोर रहेगी। उन्हें नया कर्ज जुटाने में भी मुश्किल होगी।'बैंकों को पुनर्वित्त के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से मिलने वाली रकम पर नजर रखनी होगी। इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है।इसमें अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 10 का हवाला दिया जा सकता है जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं से संबंधित है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय संदर्भ में इसकी व्यावहारिकता का जांच कर ली गई है। वित्त वर्ष 2020 के लिए खातों को अंतिम रूप देते समय 30 सितंबर 2020 तक की प्राप्तियों, भुगतान, वसूली या प्रावधानों पर विचार किया जा सकता है या वित्त वर्ष 2020 में बैंकों के खातों में अतिरिक्त छह महीनों का लेखाजोखा होगा। माना जा रहा है कि इस बारे में भारतीय सनदी लेखा संस्थान के साथ बातचीत शुरू की गई है।केंद्रीय बैंक के 7 जून के परिपत्र के तहत प्रावधान के अतिरिक्त नियमों और तीन महीने की मोहलत को शामिल करना बेहद अहम कदम हो सकते हैं।

बीपीसीएल ने विकसित की सस्ती प्रौद्योगिकी

तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कच्चे तेल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए सस्ती प्रौद्योगिकी विकसित की है। इसके तहत परीक्षण में समय भी कम लगता है। वैसे इस प्रकार की प्रौद्योगिकी के लिए अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के पास पेटेंट हैं। इस प्रौद्योगिकी को कच्चे तेल के बारे में पूरी जानकारी देने का उपकरण कहा जाता है जिसे बीपी मार्क कहते हैं। *भाषा*

अन्य राज्यों से लौट रहे मजदूरों की निगरानी कर रहे हैं बंगाल के ग्रामीण

नम्रता आचार्य
कोलकाता, 5 अप्रैल

तपन विश्वास केरल में राजमिस्त्री का काम करते हैं। वह 23 मार्च को उत्तर बंगाल के अलीपुरदौर के मदारीहाट स्थित अपने गांव पहुंचे। उनके पड़ोसियों ने उनके आने की खबर पुलिस को दे दी। बहरहाल विश्वास को 5 दिन तक पुलिस तलाश नहीं सकी। स्थानीय पंचायत के सदस्यों और पड़ोसियों ने उन पर नजर बनाए रखी। विश्वास बताते हैं कि वह अपने घर में छिपे हुए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि स्वास्थ्य जांच के लिए पुलिस पकड़ ले जाएगी।

बहरहाल विश्वास की कोविड-19 की जांच हुई और उन्हें 2 सप्ताह एकांतवास में रहने को कहा गया। वह इस समय गांव वालों की निगरानी में हैं। उन्होंने कहा, 'हर कोई बोल रहा है कि मैं बाहर गया, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है? मैं 5 दिन चलकर घर पहुंचा हूं और अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है।' कुछ दिन पहले करीब 7 विस्थापित मजदूरों ने खुद को एकांतवास में डाल दिया था, जब वे 25 मार्च को चेन्नई से वापस लौटे थे। पिछले 10 से 15 दिन के दौरान कोरोनावायरस के खौफ से पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर कामगार वापस लौटे हैं। उनका लौटना भी मुसीबत बन गया है क्योंकि स्थानीय लोग भी डरे हुए हैं। स्थानीय लोग पुलिस की भूमिका में आ गए हैं, जिससे कोविड-19 को समुदाय में न फैलने पाए। उत्तर बंगाल की एक ग्रामीण पी नीता के मुताबिक उत्तर बंगाल विस्थापित मजदूरों के बड़े केंद्रों में से एक है। ग्रामीणों ने अपनी सीमारेखा खींच दी है और अपने इलाके में अनजान चेहरा देखते ही वे पुलिस को सूचना दे रहे हैं। उनका कहना है, 'स्थानीय लोग इतने सक्रिय हैं कि बाजार के बाहर साबुन व पानी का इंतजाम किया गया है और हाथ धोए बिना किसी को बाजार में नहीं घुसने दिया जा रहा है।' नैतिक पुलिसिंग का नकारात्मक पहलू भी है। यह सामाजिक बहिष्कार का रूप ले सकता है और संसाधनों को लेकर भी लड़ाई छिड़ सकती है।

पश्चिम बंगाल में विस्थापन के तरीकों पर अध्ययन कर चुके अशोक फेलो दिलीप बनर्जी ने कहा, 'बंगाल के ग्रामीण परंपरागत रूप से जागरूक और जिम्मेदार रहे हैं। बहरहाल सामाजिक दूरी बनाने का मौजूदा स्वरूप लंबे समय तक सामाजिक बहिष्कार का रूप ले सकता है। हमें पहले ही रिपोर्ट मिलने लगी है कि कुछ गांवों में विस्थापित मजदूरों को घुसने नहीं दिया जा रहा है।'

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन इलाके में विस्थापित मजदूरों का ग्रामीणों की नजर से बचना मुश्किल हो गया है क्योंकि प्रवेश बिंदुओं खासकर नौका टर्मिनल पर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सुंदरवन क्षेत्र के लोग बड़े पैमाने पर केरल में काम करते हैं, जहां पिछले 2 सप्ताह में बड़े पैमाने पर मजदूर लौटे हैं। इस इलाके में करीब 54 आवासीय गांव/टापू हैं और गांवों तक पहुंचने का एकमात्र साधन नावें हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार ने भी एक गांव से दूसरे गांव में सब्जी और खाद्यान्य जैसे जिंसों की आवाजाही पर रोक लगा दी है।

क्षेत्र की पंचायत के एक कर्मी के मुताबिक सुंदरवन में तेजी से सिमटते एक टापू घोड़ामारा में पिछले एक पखवाड़े में 75 विस्थापित आए हैं। उन्होंने कहा कि बहरहाल स्थानीय लोग पहले ही तेज कटाव की समस्या से जूझ रहे हैं और टापू पर स्थित एक स्कूल कटाव के कारण ढहने वाला है। इस तरह से विस्थापित मजदूरों के आने से यहां के संसाधनों व आजीविका के विकल्पों पर बोझ बढ़ रहा है। उत्तर बंगाल में स्थिति और गंभीर है, जहां खेती के विकल्प सीमित हैं। अलीपुर जिले के कालचीनी के रहने वाले भुवन कहते हैं, 'हमारे पास जो भी अनाज था, खत्म हो गया। अब आमदनी का साधन नहीं है। हम लकड़ी बेचकर आजीविका चलाते हैं। अगर देशबंदी जारी रही तो हम भूख से मर जाएंगे।' 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक विस्थापन के मामले में पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर है। पिछले 2 दशक में पश्चिम बंगाल से विस्थापन बढ़ा है और रोजगार की संभावना न होने के कारण लोग केरल, तमिलनाडु, दिल्ली व महाराष्ट्र भागे हैं।

रविवार को यूपी के प्रयागराज में वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के कारण हुई देशबंदी को देखते हुए कॉलोनी में आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया *फोटो-पीटीआई*

'कोविड संबंधी कर चिंता को मानें असाधारण'

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 5 अप्रैल

अगर कोई प्रवासी भारतीय कोरोनावायरस और उसके कारण हुई देशबंदी की वजह से 182 दिन से ज्यादा देश में फंस गया है तो क्या भारत में उसकी कर देनदारी बनेगी? क्या सीमा पार के कर्मचारी अगर लंबे समय से भारत में फंसे हुए हैं तो क्या स्थाई प्रतिष्ठान से संबंधी कर चिंता उसके विदेशी नियोक्ता को करनी होगी?

वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से उपजी इस तरह की कर संबंधी चिंता का समाधान करते हुए ऑर्गेनाइजेशन आफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऐंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) ने अपने दिशानिर्देश लेख में सुझाव दिया है कि इस तरह की स्थिति को 'असाधारण और अस्थाई' माना जाना चाहिए और इस तरह के मामलों को निवास या पीई की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए।

इस नोट में बताया गया है कि कोविड-19 के कारण आवाजाही पर रोक लगने से कर संधियों के सामान्य प्रावधान प्रभावित हुए हैं। भारत के कर अधिकारी ओईसीडी के दिशानिर्देश पर विचार कर रहे हैं और इन पहलुओं पर स्पष्टीकरण के लिए जल्द ही परिपत्र और अधिसूचना आ सकते हैं।

कोविड के कारण पूरी दुनिया में कामकाज के तरीके बदल गए हैं और ज्यादातर कर्मचारी घरों से काम कर रहे हैं, वहीं अन्य तमाम लोग कुछ शहरों व देशों द्वारा जारी लॉकडाउन के आदेश विदेश में फंसे हो सकते हैं। ओईसीडी ने कहा है कि कर संधियों से यह तय करने में मदद मिलेगी कि ऐसे मामले में व्यक्ति या कंपनी पर कर लगाना किसके अधिकार क्षेत्र में है।

देश में कोरोनावायरस पर काबू पाने के लिए भारत ने 24 मार्च को 21 दिन की देशबंदी की घोषणा की थी।

ओईसीडी के सेंटर फार टैक्स पॉलिसी ऐंड एडमिनिस्ट्रेसन के निदेशक पास्कल सेंट अमंस ने एक नोट में सभी देशों से मिलजुलकर काम की अपील करते हुए लिखा है, 'कोविड-19 संकट के कारण उपजी असाधारण परिस्थितियों के कारण विभिन्न देशों के बीच कर के मसलों पर असाधारण स्तर के समन्वय और सहयोग की जरूरत है, जिससे कि कर्मचारियों व नियोक्ताओं के अनुपालन और प्रशासनिक लागत को कम किया जा सके।' इस मामले को लेकर संबंधित देशों की ओर से अनुरोध पर यह दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

इस नोट में स्थायी प्रतिष्ठान स्थापित करने, विदेशी कंपनी की उपस्थिति पर कर (प्रभावी प्रबंधन की जगह) और सीमा पार काम करने वाले लोगों संबंधी चिंता और किसी व्यक्ति के आवास में बदलाव संबंधी चिंता का समाधान करने की कवायद की गई है।

ओईसीडी का कर पर नोट

- अगर कोई व्यक्ति किसी देश में कोरोना के कारण फंस गया है तो स्थिति को असाधारण माना जाए
- इसे पीई की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, देशों में सहयोग की जरूरत
- भारत के कर विशेषज्ञों ने परामर्श का स्वागत करते हुए कहा कि इससे घटेंगी कर जटिलताएं

ओईसीडी ने पाया कि कोविड-19 के कारण इस बात की संभावना कम है कि स्थायी प्रतिष्ठान के निर्धारण को लेकर कोई बदलाव आएगा।

इसमें कहा गया है, 'कोविड-19 संकट के कारण कर्मचारी के काम करने की जगह में अपवादस्वरूप और अस्थायी बदलाव जैसे घर से काम करने से नियोक्ता का नया स्थायी प्रतिष्ठान नहीं बनता।' इसमें आगे कहा गया है कि इसी तरह से कोविड 19 के कारण कर्मचारियों या एजेंटों की स्थिति में अस्थायी रूप से बदलाव से कारोबार का स्थाई प्रतिष्ठान नहीं बनता है। सामान्यतया पीई या देश में कर योग्य उपस्थिति तब मानी जाती है जब प्रमुख कर्मचाती उस न्यायक्षेत्र में काम करते हैं। बहरहाल ओईसीडी ने कहा है कि इस तरह की स्थिति पैदा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि संधियों में सामान्यतया स्पष्ट रूप से पीई में स्थायित्व की सीमा तय की गई है।

शार्दूल अमरचंद मंगलदास ऐंड कंपनी की गौरी पुरी ने कहा कि असाधारण समय को देखते हुए सिफारिशें स्वागतयोग्य हैं, ऐसी स्थिति में विशेष कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिससे सीमा पार कामगारों को कर जटिलता से बचाया जा सके। पुरी ने कहा, 'उदाहरण के लिए अगर कोई विशेषज्ञ भारत की यात्रा पर हो और वह देशबंदी में फंस गया हो तो कर संबंधी मसला उठ सकता है। उसके विदेशी नियोक्ता को पीई को लेकर चिंता हो सकती है।' नांगिया एंडरसन कंसल्टिंग के चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा कि ओईसीडी सचिवालय की ओर से जारी नोट से निस्चित रूप से संकट की इस घड़ी में कारोबारियों को मदद मिलेगी।

कर अधिकारियों को घर से काम करने की सुविधा

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 5 अप्रैल

वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने 1,700 से ज्यादा कर अधिकारियों को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सुविधा का इस्तेमाल करके घर से काम करने की सुविधा दे दी है। कोरोनावायरस के कारण देशबंदी को देखते हुए जीएसटी के आईटी की रीढ़ कहे जाने वाले जीएसटीएन ने यह सुविधा दी है।

इससे अधिकारियों को विभिन्न जीएसटी आवेदनों जैसे पंजीकरण आवेदनों, रिफंड आवेदन, ऑडिट, आकलन, अपील आदि पर सुरक्षित तरीके से काम करने की सुविधा मिल गई है।

रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, 'जीएसटीएन ने विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाले अपने अधिकारियों को देशबंदी की अवधि के दौरान उनके कार्यालय की एक्सेस मुहैया कराई है। कंपनी ने अनुरोध के आधार पर ऑफिस नेटवर्क की सुरक्षित एक्सेस की सुविधा मुहैया कराई है।

इस तरह से कंपनी ने कर अधिकारियों को पंजीकरण से जुड़े 20,273 मामलों पर काम करने की सुविधा दे दी है, जो देशबंदी के पहले 10 दिन में 25 मार्च से 3 अप्रैल के बीच आए हैं। इनमें 10,077 मामले नए पंजीकरण के, 3,377 मामले प्रमुख संशोधन और 3,784 मामले आवेदन द्वारा निरस्तीकरण से जुड़े हैं। इनके अलावा 1,966 मामले स्वत: स्फूर्त रद्द होने और 1,069 मामले निरसन से जुड़े हैं।

दरअसल इससे करदाताओं को समय से रिफंड मिल सकेगा, जिससे जुड़े 7,876 मामले इस दौरान आए हैं और इससे उन्हें नकदी से संबंधी समस्या नहीं आएगी। जीएसटीएन ने कहा, 'इससे अधिकारियों को फाइलें जमा होने से बचने में मदद मिलेगी। अगर देशबंदी के दौरान मामले नहीं निपटाए जाते तो ऐसा हो सकता था।' जीएसटीएन 29 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आईटी सेवाएं मुहैया कराने के साथ जीएसटी दाखिल करने वाले 1.23 करोड़ करदाताओं को सुविधा मुहैया कराता है।

खर्च को लेकर इतनी कंजूसी क्यों दिखा रही है सरकार?

केरल के साथ ही अन्य राज्य केंद्र को उच्चतम न्यायालय में घसीटने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी वजह है कि केंद्र उनके 40,000 करोड़ रुपये जीएसटी बकाये के साथ ही 40,000 करोड़ रुपये की लंबित एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान नहीं कर रही है। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए केरल के वित्त मंत्री **थॉमस इसाक** ने **दिलाशा सेठ** के साथ बातचीत में कहा कि यदि केंद्र सरकार उधारी सीमा में जीडीपी के 1 फीसदी का इजाफा नहीं करती है तो राज्य को कठिन वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। पेश हैं मुख्य अंश...

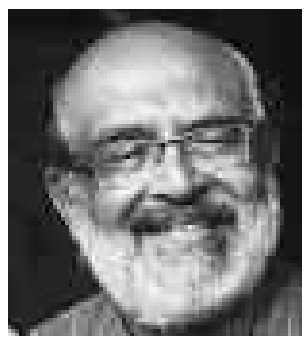

कोरोनावायरस के मुकाबले के लिए आप केंद्र सरकार की तैयारियों पर आपका आकलन क्या है? क्या 1.7 लाख करोड़ की राहत पर्याप्त है?

पेश की गई राहत निराशाजनक है। एक ओर जब केंद्र सरकार ने देशबंदी कर रखी है और अधिकांश लोग अपना रोजगार गंवा बैठे हैं तब उसने उन्हें 500 रुपये प्रति महीने की मामूली पेशकश की है। निस्संदेह राशन मुफ्त और अतिरिक्त दिया जा रहा है लेकिन यदि आप बाकी जगहों पर दिए जा रहे राहत को देखें तो यह पर्याप्त नहीं है। ब्रिटेन स्?वरोजगार कर रहे लोगों और कामगारों को 80 फीसदी वेतन का भुगतान कर रहा है।

केंद्र सरकार को किन क्षेत्रों में आवंटन बढ़ाने की जरूरत है?

सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को संस्थागत करने का यह सबसे उपयुक्?तसमय है। पहला, असंगठित क्षेत्र के लिए सार्वभौमिक पेंशन योजना शुरू करना अच्छा रहेगा, जो केवल गरीबी रेखा से नीचे के लिए लोगों तक सीमित न हो। 1,000-2,000 रुपये तक की पेंशन योजना शुरू की जानी चाहिए। केरल सरकार 55 लाख लोगों को 1,200 रुपये देती है जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 6.5 लाख रुपये की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मजदूरी में की गई बढ़ोतरी संदेह के घेरे में है क्योंकि इसका लाभ केवल 100 दिनों का रोजगार पाने वाले मजदूर को ही मिलेगा। कोविड के दौरान कोई भी मनरेगा कार्यक्रम नहीं चलेगा। प्रत्येक मरनेगा मजदूर के खातों में पिछले वर्ष के मासिक औसत भुगतान के आधार पर पैसा भेजा जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किए जाने वाले आवंटन को भी दोगुना किया जाना चाहिए।

केरल सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये के कोविड पैकेज की घोषणा की है। राज्?यकी दबावग्रस्?तवित्तीय स्थिति और केंद्र के पास पड़े बकाया के बीच आप बाजार से कितना उधार लेंगे? केंद्र को राज्यों की कोई परवाह नहीं है। हमें संकट से निकलना होगा। कम से कम उसे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जैसे हमारे बकाये का तो भुगतान कर देना चाहिए। उसे राज्यों को जीडीपी की अतिरिक्?त1 फीसदी उधारी लेने की अनुमति देनी चाहिए। हमने अगले वर्ष के लिए 27,000 करोड़ रुपये की उधारी की अनुमति दी है और उसका आधा अग्रिम उधार लेना चाहते हैं और इसे बंदी के दौरान अप्रैल से मई के बीच खर्च करना चाहते हैं।

क्या आपको लगता है कि केंद्र आपकी उधारी सीमा को बढ़ाएगा, क्योंकि 2020-21 में अर्थव्यवस्था में गिरावट आने के आसार हैं?

हम बड़ा जोखिम लेने जा रहे हैं और इसका आगे गंभीर परिणाम हो सकता है। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। राष्ट्रीय आय वित्त वर्ष 2021 में नकारात?क रहेगी। वैश्विक वृद्धि भी नकारात्मक होने जा रही है। अमेरिका इतना संरक्षणवादी है कि उसने 2 लाख करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। दूसरे देश भी खर्च रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार खर्च करने में इतना कंजूसी क्यों कर रही है? मुझे भरोसा है कि केंद्र सरकार परिस्थितियों को देखते हुए अपने रुख में परिवर्तन लाने पर मजबूर हो जाएगी।

बकाया जीएसटी को लेकर आपकी केंद्र से बात कहां तक पहुंची है?

केरल को 3,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह केरल जैसे राज्य के लिए बड़ी राशि है। दुर्भाग्य यह है कि मार्च के आखिर तक केंद्र सरकार ने गैर कानूनी तरीके से राज्यों का 40,000 करोड़ रुपये बकाया रोके रखा। उसने एकीकृत जीएसटी को संचित निधि में शामिल कर रखा है। इसमें हमें सिर्फ 42 प्रतिशत दिया गया है, जो बंटवारे से आता है, जबकि आईजीएसटी का 50 प्रतिशत राज्यों को मिलना चाहिए। हमें करीब 40,000 रुपये नुकसान हो रहे हैं। जीएसटी और उपकर का संग्रह भी कठिन हो सकता है। मुआवजा की जरूरतें तेजी से बढ़ेंगी, लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार आपको भुगतान करेगी? मार्च में संग्रह खराब रहा। अप्रैल में देशबंदी की वजह से बमुश्किल कुछ होनाा है। ऐसे में केंद्र सरकार को हमें मुआवजा देना चाहिए। वह जीएसटी परिषद को उधारी लेने और भुगतान करने व एक साल और उपकर को बढ़ाने का काम कर सकती है।

कानून जीएसटी परिषद को उधारी लेने की अनुमति देता है?

मुआवजा कोष है, उसमें अन्य धन भी डाला जा सकता है। हमारा मानना है कि ऐसा हो सकता है। अगर केंद्र सरकार उधार लेना नहीं चाहती है तो वह कोष को उधारी की अनुमति दे सकती है। यह ऐसे कदम हैं, जो केंद्र सरकार के वित्त पर असर डाले बगैर उठाए जा सकते हैं।

नीति आयोग ने एनजीओ, संयुक्त राष्ट्र, उद्योग निकायों से साधा संपर्क

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली 5 अप्रैल

कोरोनावायरस महामारी से मुकाबला के लिए सरकार ने गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), उद्योग संघों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क कर उनका सहयोग मांगा है। सरकार की पहुंच और उसके कदमों को सहयोग देने के लिए उनका सहयोग मांगा गया है।

इस पहल को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 29 मार्च को नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी अमिताभ कांत की अगुआई में गठित अधिकार प्राप्त समूह द्वारा पूरा किया जा रहा है। नीति आयोग कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिक्रिया के लिए एनजीओ, निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समन्वय करेगा।

समिति ने निजी क्षेत्र और स्टार्टअप में आपस में संवाद भी आरंभ कराया है ताकि स्वास्थ्य उपकरण और पीपीई के उत्पादन के लिए साझेदारी कायम की जा सके।

समिति ने 30 मार्च से 6 अप्रैल के बीच फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर आफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री (फिक्की), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) सहित उद्योग संगठनों, नागरिक समाज के समूहों और विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ छह बैठकें की हैं।

अगवा, बायोडिजाइन इनोवेशन लैब, क्योर एआई ड्रोन मैप्स, एमफाइन, माइक्रोगो, स्टाक जैसी स्टार्टअप अभिनव वेंटिलेटर डिजाइन, परीक्षण उपकरणों और ट्रैकिंग उपायों पर काम कर रही हैं। इन सभी से अलग अलग मिलकर इनके उत्पादन के दायरे और संभावित योगदानों का समझा गया है। नीति आयोग की ओर से प्रेस को जारी किए गए बयान में ये जानकारी दी गई है।

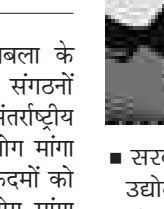

वैश्विक महामारी **कोरोनावायरस**

करीब 92,000 एनजीओ और नागरिक समाज के संगठनों को लिखे पत्र में सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग ने बेघरों और दिहाड़ी मजदूरों को आश्रय प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य और सामुदायिक कर्मियों को व्यक्तिगत रक्षा उपकरण, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन के वितरण में उनकी भागीदारी की मांग की है।

रोकथाम, स्वच्छता, सामाजिक दूरी, पृथक्करण और सामाजिक कलंक से लड़ने में एनजीओ से विशेष तौर पर स्थानीय भाषाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही है।

- सरकार ने गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संघों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क कर मांगा सहयोग
- नीति आयोग कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों को लेकर विभिन्न संगठनों के साथ समन्वय करेगा
- नीति आयोग की समिति ने निजी क्षेत्र और स्टार्टअप के बीच भी संवाद शुरू कराया है, जिससे स्वास्थ्य उपकरण और पीपीई के उत्पादन के लिए साझेदारी की जा सके
- हॉटस्पॉट पहचानने, बुजुर्गों, बच्चों, दिव्यांगों, किन्नरों को सेवाएं देने में एनजीओ करेंगे मदद

नीति आयोग ने एनजीओ से प्रशासन को हॉटस्पॉट की पहचान करने में मदद करने और बुजुर्गों, दिव्यांगों, बच्चों और किन्नरों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए स्वयंसेवकों और देखभाल करने वालों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है।

प्रत्येक एनजीओ और नागरिक समाज के संगठन को उसे एफसीआरए जानकारियों के साथ किस तरह की मदद मुहैया करा रहे हैं व स्थान की जानकारी देनी होगी। उन्हें खर्च की गई राशि, समर्थन गतिविधियों की अवधि और पेश होने वाली चुनौतियों के साथ अपने सुझावों को भी भेजना होगा।

उद्योग प्रतिनिधियों ने भी अधिकार प्राप्त समूह के साथ जन जागरूकता में चलाई गई गतिविधियों, परोपकार, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर भोजन पकाने के लिए और उसे मुफ्त बांटने के लिए सीएसआर के तहत चलाए जा रहे फैक्टरी रसोई, एकांतवास और ठहरने की सुविधाओं के लिए फैक्टरी अस्पतालों, परिसरों, अतिथि गृहों को उपलब्ध कराने जैसे कदमों का साझा किया है।

समिति के सदस्यों में पीएसए विजयराघवन, एनडीएमए के सदस्य कमल किशोर, सीबीआईसी के सदस्य संदीप मोहन भटनागर सहित गृह और विदेश मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं।

बीएस सूडोकू 3707

परिणाम संख्या 3606

	4						6	
		9	5			2		
1		3						
	7				8	9		
		4			7		8	
	8			4		6		
			6	7				1
			8	9		7		
				3	4			

2	1	8	9	3	5	4	7	8
4	5	9	6	8	7	1	2	3
7	8	3	1	4	2	9	5	6
1	6	2	7	9	4	3	8	5
5	9	7	8	1	6	2	9	4
9	4	8	2	5	3	7	6	1
6	2	1	3	6	9	5	4	7
3	9	5	4	7	8	6	1	2
8	7	4	5	2	1	8	3	9

कैसे खेलें?

हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम

वायरस फैलने के कारण भारत ने लगाई जांच किट के निर्यात पर रोक

रॉयटर्स
नई दिल्ली, 5 अप्रैल

भारत ज्यादातर डाइग्नोस्टिक टेस्टिंग किट का निर्यात रोक रहा है, क्योंकि तीन सप्ताह के देशबंदी के बावजूद दक्षिण एशियाई देश में कोरोनावायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 3,350 पहुंच गई है।

भारत ने वेंटिलेटर, मास्क व अन्य बचाव के उपकरणों सहित कुछ दवाओं के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी जरूरत मरीजों व मेडिकल कर्मियों दोनों को है। इस सिलसिले में शनिवार को नए दिशानिर्देश जारी हुए हैं।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुरोध किया कि मलेरिया रोधी दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति की जाए, जिसे कोविड-19 के उपचार की संभावित दवा के रूप में चिह्नित किया गया है। शनिवार को ह्वाइट हाउस के प्रवक्ता जुड डीरे ने एक ट्वीट में कहा- दोनों नेता दवाओं की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के मसले पर संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान कामकाज सामान्य तरीके से जारी रहना सुनिश्चित हो सके। भारत ने एक ब्रीफिंग नोट में कहा है कि दोनों नेता भारत-अमेरिका साझेदारी की पूरी ताकत लगाने पर सहमत हुए हैं, जिससे कोविड-19 पर काबू पाया जा सके।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 39

राजकोषीय गतिरोध

देश में कोविड-19 महामारी के प्रसार से निपटने संबंधी प्रतिक्रिया काफी हद तक राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर निर्भर है। इस पर आमतौर पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना दिया जाना चाहिए। इस महामारी से लड़ने में राज्य सरकारें ही अग्रिम मोर्चे पर हैं। ऐसे में जबकि इन सरकारों के राजस्व में पहले ही भारी गिरावट की आशंका है, यह खर्च उन पर और अधिक बोझ डालने वाला है। उदाहरण के लिए मार्च में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के स्तर से नीचे फिसल गया। आने वाले महीनों में भी यह दबाव में रह सकता है। इसके अलावा राज्य सरकारों को जीएसटी संग्रह में महीनों से हो रही कमी का हर्जाना भी नहीं मिल सका है। केंद्र सरकार का कहना है कि वह केवल विलासिता की वस्तुओं और खराब मानी जाने वाली वस्तुओं से संग्रहीत उपकर के माध्यम से ही क्षतिपूर्ति दे सकती है। इसका चालू वर्ष में राज्यों के बजट पर भारी असर होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट का अनुमान जताया जा रहा है। जीएसटी के दायरे के बाहर की वस्तुओं मसलन शराब, पेट्रोलियम उत्पादों और स्टांप शुल्क आदि से होने वाले राजस्व संग्रह पर भी असर पड़ेगा।

बजट को लेकर भारी बाधा का सामना कर रही कई राज्य सरकारों ने या तो व्यय कटौती का निर्णय लिया है या फिर वे अपने कर्मचारियों का वेतन स्थगित कर रही हैं। बहरहाल चुनौती का आकार देखते हुए कहा जा सकता है कि वे ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगी। कुछ राज्य सरकारों ने महामारी से निपटने के लिए केंद्र से सहायता मांगी है और वे राजकोषीय घाटे की सीमा में भी एक फीसदी का इजाफा कर रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों के वित्त को सुधारने के लिए 17,287 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय किया है और रिजर्व बैंक ने भी बकाये की सीमाओं में इजाफा किया है इसलिए कहा जा सकता है कि राजकोषीय समस्याओं से अधिक व्यवस्थित तरीके से निपटा जा सकेगा।

यह स्पष्ट है कि बजट संबंधी बाधाओं के चलते केंद्र और राज्य दोनों महामारी से निपटने में सक्षम नहीं हैं। व्यय में इजाफा भी नहीं किया जा सकता। शायद आसान यही है कि राज्यों के बजट घाटे की सीमा एक फीसदी बढ़ा दी जाए। हालांकि यह भी तय नहीं कि इतना करना पर्याप्त होगा या नहीं। सरकारी बॉन्ड की आपूर्ति के अनुमान के साथ बॉन्ड प्रतिफल में इजाफा हुआ है। मांग कम है लेकिन बॉन्ड आपूर्ति बढ़ी है क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बिकवाली की है। यह भी तय है कि केंद्र सरकार इस वर्ष राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी लेकिन उसने ऋण योजना में बदलाव नहीं किया है। इससे वित्तीय बाजार भ्रमित हुए हैं।

राजकोषीय बाधाओं से पारदर्शी ढंग से निपटना जरूरी है। पहली बात, जिस पैमाने पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है उसे सामने रखा जाना चाहिए। केवल तभी सरकार जरूरी संसाधन जुटा सकेगी तथा केंद्र और राज्यों के बीच संभावित वितरण कर सकेगी। सरकार को केंद्रीय बैंक से भी मशविरा करना होगा। कई टीकाकारों का कहना है कि सरकारी बॉन्ड सीधे आरबीआई को बेचे जाएं। हालांकि फिलहाल यह आसान तरीका दिख रहा है लेकिन सरकार को दीर्घावधि प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी व्यय में इजाफा होना अपरिहार्य है। ऐसे में केंद्र को पारदर्शी तरीके से काम करना होगा। इससे न केवल राज्यों से वित्तीय दबाव हटाने में मदद मिलेगी बल्कि वित्तीय बाजारों में भी स्पष्टता आएगी। सरकारी हस्तक्षेप की प्रकृति भी यह निर्धारित करेगी कि भारत कितनी जल्दी इस महामारी को थामने में कामयाब होगा और कितनी जल्दी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी।

अजय मोहंती

मोदी और उनके संदेश की क्या है राजनीति ?

मोदी जानते हैं उन्हें किसे संबोधित करना है, किसकी अनदेखी करनी है और किसे उपकृत करना है। आप ताली, थाली, दीया और मोमबत्ती का मजाक उड़ाते रहिए मोदी को परवाह नहीं है।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

समाचार जगत में दुष्ट कोरोनावायरस के प्रसार की खबरों ने तमाम अन्य खबरों को पीछे छोड़ दिया है और लगता नहीं कि निकट भविष्य में हालात बदलने वाले हैं। परंतु मैं इससे ऊब चुका हूं। कम से कम इस सप्ताह के लिए इससे इतर पुरानी राजनीतिक बातें करना चाहता हूं लेकिन दिक्कत यह है कि राजनीति भी काफी हद तक स्थगित नजर आ रही है।

राजनीतिक बातों पर भी कोरोनावायरस का साया है। आइए देखें कि अपने सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को लेकर नरेंद्र मोदी ने संदेश देने के मोर्चे पर कैसा काम किया है। बतौर संदेशवाहक उनको उन्हें जो वरदान हासिल है वह मनमोहन सिंह से लेकर राजीव गांधी तक उनके आठ पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों को भी हासिल नहीं था: यानी भारतीयों के एक बड़े तबके को सीधे और आश्वस्त करने वाले ढंग से संबोधित करना। ये भारतीय उनकी बात को देववाणी मानते हैं और पोप के आदेश की तरह आज्ञा पालन करते हैं। आम लोगों, खासकर अपने मतदाताओं के दिलोदिमाग को समझने में वह इंदिरा गांधी को टक्कर देते हैं। ये ही कारण हैं कि अपनी सरकार की ओर से हर संदेश वही दे रहे हैं। वह तमाम वक्तव्य देते हैं। कुछ साधारण बातें करते हैं तो कुछ तीखे तंज, बाकी का काम अपने आप हो जाता है।

जैसा कि गत शुक्रवार को दिए उनके भाषण को लेकर हुआ, भाषण पूरा होने के एक घंटे के भीतर या भाषण के बीच में ही उनकी पूरी कैबिनेट, पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी, सोशल मीडिया पर उनके कार्यकर्ता, आरएसएस और भाजपा से जुड़े बौद्धिक सभी ने भाषण के हिस्से ट्वीट करने शुरू कर दिए। कोरोनावायरस को लेकर उन्होंने जो चार भाषण दिए, उनका संपूर्ण कथन उपरोक्त ट्वीट से जुटाया जा सकता है। जब वह बोलते हैं तो ये तमाम लोग उनकी बात को प्रतिध्वनित करते हैं। सब उनकी जुबान में बोलते हैं। संदेश की बात करें तो अलग-अलग आवाजों में भी उसका मूल स्वरूप बरकरार रहता है। इसमें इस बात से सहयोग मिलता है कि वह चाहे जो कहें या करें, उनके लोग और उनके मूल मतदाता उनकी हर बात पर यकीन करते हैं। यदि वह कुछ गड़बड़ भी करते हैं, जैसा कि नोटबंदी के दौर में हुआ, तो भी प्रशंसक उनको क्षमा कर देते हैं। पिछले दिनों हुई मन की बात को याद कीजिए कैसे उन्होंने देश के गरीबों से असुविधा के लिए माफी मांगी थी और लाखों दिल पसीज गए थे।

वह कभी यह नहीं बताते कि वह लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। पिछले चार भाषणों जिनमें राष्ट्र के नाम दो संबोधन, मन की बात और शुक्रवार का दीया जलाने वाला संदेश शामिल था, उन्हें याद कीजिए। वह लोगों के लिए क्या कर रहे हैं यह बताने के बजाय वह उन्हें बताते हैं कि लोगों को अपने लिए और खुद उनके लिए क्या करना चाहिए। स्वच्छ भारत से लेकर एलपीजी सब्सिडी त्यागने तक, नोटबंदी से लेकर अब कोविड-19 तक उन्होंने जितनी पहल की शुरुआत की है, हर बार उन्होंने आम जन से कुछ न कुछ करने को कहा। यह बात लोगों को जवाबदेह बनाती है। भला कौन नहीं चाहता कि उसे गंभीरता से लिया जाए। वह भी इतने महत्त्वपूर्ण नेता द्वारा।

कोरोनावायरस से जुड़े भाषणों में उन्होंने यही किया। पहले भाषण में उन्होंने कहा कि वह लोगों से जीवन का एक सप्ताह मांग रहे हैं, लेकिन बात वहीं रह गई। शायद वह आने वाले समय के लिए जनता को तैयार करने का नुस्खा था।

उन्होंने एक दिन के जनता कर्फ्यू की मांग की और हममें से कई ने अंदाजा लगा लिया था कि यह एक लंबे लॉकडाउन के पहले की प्रक्रिया है। उन्होंने चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस तथा अनिवार्य सेवाओं से जुड़े अन्य लोगों के लिए तालियां बजाने और उनका उत्साह बढ़ाने की बात कही। उन्होंने घंटियां बजाने और थाली बजाने का मशविरा देकर लोगों को और उत्साहित किया। आप भले ही इस बात पर कितना भी हंसें। देश भर के करोड़ों लोगों ने ऐसा किया और प्रसन्न भी हुए। कई लोगों ने ऐसा करते हुए हद पार कर दी। जहां तक वायरस की बात है, वह तो जिंदा वस्तु तक नहीं है तो वह भला शोर से क्यों परेशान होगा। मोदी ने भी कोई वादा नहीं किया था, न ही इससे कुछ हुआ। मोदी के माफी मांगने में भी एक खास रुझान महसूस किया जा सकता है। नोटबंदी के बाद जब पूरा देश हलाकान था तब गोवा में उन्होंने ऐसा ही एक भाषण दिया था। रुंधे गले से उन्होंने कहा था कि अगर उनके इरादों या उनके कदमों में कोई खामी हो तो वह देश द्वारा दिया जाने वाला कोई भी दंड भुगतने को तैयार हैं। जाहिर है इतने विनम्र नेता को भला कौन दंडित करेगा। नोटबंदी वैसी ही बड़ी भूल थी जैसी माओ द्वारा चीन में गौरेयों के खिलाफ हमला। परंतु यहां एक ताकतवर प्रधानमंत्री था जिसने नेक इरादों से यह बड़ा जोखिम उठाया था। वह लोगों से उनके और देश के हित में मामूली त्याग करने को ही तो कह रहा था।

मन की बात कार्यक्रम में कोरोनावायरस को लेकर मांगी गई माफी में ज्यादा बारीकी निहित थी। वह उस गड़बड़ी के लिए माफी नहीं मांग रहे थे जो उन्होंने उत्पन्न की थी बल्कि वह इस साहसी कदम से हो रही असुविधा की माफी मांग रहे थे। वह बड़ा कदम जो देश को कोरोना से बचाने के लिए उठाया गया था। ध्यान रहे उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के जबरिया विस्थापन के संकट का उल्लेख तक नहीं किया।

इससे तीन सबक मिलते हैं: पहला मोदी अपने संदेश में कोई वादा नहीं करते। दूसरा, वह हमेशा आप से अपने लिए और राष्ट्र के लिए कुछ करने को कहते हैं। तीसरा, वह कभी किसी बात का पश्चाताप नहीं करते। वह कभी यह तक नहीं कहते कि हम इस काम को बेहतर ढंग से कर सकते थे।

चौथा सबक, उन्हें अच्छी तरह पता है कि किसे संबोधित करना है, किसकी अनदेखी करनी है, किसकी नहीं करनी है और उसे लाभान्वित करना है। यानी उनकी आलोचना करने वाले, टीकाकार कथित उदारवादी और ऊंचे तबके के बुर्जुआ उनकी बातों का मखौल उड़ाते हैं। ताली-थाली, दीया-बाती को लेकर बनते मजाक आदि बनाते हैं लेकिन मोदी के भाषण और संदेश उनके लिए नहीं हैं।

दूसरा तबका जिसे वह संबोधित नहीं कर रहे लेकिन जिसकी वह अनदेखी भी नहीं कर सकते वह हैं गरीब। उन्हें बहुमत इन्हीं लोगों से मिलता है लेकिन वे उनकी बहस को संचालित नहीं करते। गरीब लोग चतुर होते हैं, राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होते हैं और सवाल बहुत करते हैं। उन्हें जोखिम में क्यों डालना? मध्य वर्ग का मतदाता इनसे बाहर है और एजेंडा तय करता है। अगर वह सवाल करता तो वह थाली या मोमबत्ती लेकर बालकनी में क्यों आता? गरीबों को मोदी नकदी, एलपीजी, शौचालय, आवास आदि के माध्यम से संबोधित करते हैं। जब पैसे से काम हो रहा हो तो संदेश की जरूरत क्या है। गरीबों को उनकी सीधी मदद पहले की तुलना में बहुत बेहतर रही है। हमें अक्सर यह आलोचना सुनाई देती है कि मोदी देश के लोगों को बचकाना बना रहे हैं। ताली, थाली, मोमबत्ती और गो कोरोना गो जैसी चीजों को भला और क्या कहेंगे? मोदी हमें समझते हैं थाली प्रकरण में हम ऐसा देख चुके हैं। व्हाट्सऐप पर ऐसे संदेश भेजे गए मानो थाली बजाने से वायरस मर जाएगा। गत शुक्रवार को एक जानेमाने चिकित्सक और भारतीय चिकित्सा महासंघ के पूर्व मुखिया ने भी ऐसी ही बेवकूफाना बात की कि इससे कोरोनावायरस खत्म हो जाता है। अगले भाषण में उन्होंने लोगों को बालकनी या सड़कों पर नहीं निकलने को कहा और सामाजिक दूरी बनाने पर जोर दिया। अगर कोई कहता है कि वह मोदी का मस्तिष्क पढ़ सकता है तो वह या तो झूठा है या फिर आइन्स्टीन का अवतार। आप खुद को मोदी की जगह रखकर देखिए। अगर मैं खुद को रखूं तो मुझे ऐसा नजर आता है: ओह! लोग कितने बचकाने हैं। लेकिन आज्ञाकारी बचकाने। आज्ञापालन के क्रम में वे अति कर सकते हैं लेकिन मैं उन्हें सतर्क करता रहूंगा।

मोदी जीत रहे हैं। उन्हें शिकायत क्यों होगी? वह उन आलोचकों की फिक्र क्यों करें जो उन पर आरोप लगाते हैं कि वह मतदाताओं को बचकाना बना रहे हैं। जनता तो बच्चा बन के खुश है।

आपातकालीन उपाय अपनाने का आया उचित समय

बाअदब

सोमशेखर सुंदरेशन

जब हालात जंग जैसे आपातकालीन हों तो सोच में भी बदलाव लाना होता है, उस वक्त शांतिकालीन नीतिगत ढांचा काम नहीं आता है।

यह तय है कि हालात बहुत खराब हैं। कोविड-19 महामारी के आगमन के बाद पिछले कुछ दिनों में कारोबारी गतिविधियों से जुड़ी हर गतिविधि एकदम अप्रत्याशित, असाधारण और कल्पना से परे रही है। केवल मॉल, न्यायालय, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बसें और ट्रेन ही नहीं बल्कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और कार्यालय भी बंद कर दिए गए हैं। केवल स्वास्थ्य सेवाएं और किराने की दुकानें खुली हैं। हर तरह का कारोबार थम गया है। ऐसे असामान्य हालात में हमें असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने राह दिखाई है। अनुच्छेद 142 के प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम समय सीमाओं को आगे बढ़ा दिया है। कोई भी मामला यदि न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तो उसे एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय को पता है कि मौजूदा परिस्थितियों में लोगों का न्यायालय तक पहुंचना असंभव है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी तरह का भ्रम दूर करने के लिए अनुच्छेद 141 का स्पष्ट उल्लेख किया और सभी उच्च न्यायालयों को यह आदेश दिया कि वे अपने यहां तथा अपने अधीनस्थ न्यायालयों में इस आदेश को लागू करें। अनुच्छेद 141 कुछ और नहीं कहता बल्कि इस महत्त्वपूर्ण सिद्धांत को सामने रखता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित कानून भारत के तमाम न्यायालयों पर लागू होगा। न्यायालय को शायद ही कभी यह याद दिलाने की आवश्यकता पड़ती है कि यह प्रावधान संविधान में मौजूद है। परंतु आज देश जिस आपातकालीन परिस्थिति में है, उसके कारण न्यायालय को यह स्पष्ट करना पड़ा कि यह कोई सामान्य प्रशासनिक निर्णय नहीं है बल्कि यह एक ऐसा निर्णय है जो पूरे देश पर न्यायिक असर डालेगा।

इस परिदृश्य में अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की निगरानी करने वाले हमारे विधिक तंत्र के हर अंग को नए सिरे से तैयारी करनी होगी और इस बारे में नए ढंग से सोचना होगा कि मामलों से कैसे निपटा जाए। वित्त मंत्रालय और कंपनी मामलों के मंत्रालय ने यह घोषणा कर दी हैकि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया प्रक्रियाओं की शुरुआत करने के लिए जरूरी समय-सीमा में इजाफा किया जाएगा। यदि कोई कॉर्पोरेट कर्जदार एक लाख रुपये तक की राशि का कर्ज चुकाने में अक्षम रहता है तो कर्जदाता निस्तारण प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अब इस सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जा रहा है। इसके साथ ही यह घोषणा भी की गई कि 30 अप्रैल तक हालात का विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद सरकार जरूरत पड़ने पर उक्त प्रावधानों को निलंबित भी कर सकती है।

यह देखना सुखद है कि सरकार शुरुआत से ही अर्थव्यवस्था में आने वाली दिक्कतों के बारे में सोच रही है लेकिन उपरोक्त उपाय निरर्थक साबित हो सकते हैं। यदि चार सप्ताह पहले यह कहा जा सकता है कि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया व्यवस्था को 30 अप्रैल से स्थगित भी किया जा सकता है तो इसका अर्थ यह है कि जो लोग इसे लेकर जरा भी संशय में हैं वे 30 अप्रैल के पहले अपने स्तर पर कार्यवाही की शुरुआत भी कर देंगे। यदि ऐसा हुआ तो ऐसी प्रक्रियाओं की शुरुआत करने की हड़बड़ी सामने आएगी। इस बीच राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट ने कोविड-19 से निपटने के क्रम में अपना कामधाम लगभग बंद कर दिया है। संक्षेप में कहें तो अर्थव्यवस्था को यही संकेत जा रहा है कि कोविड-19 के प्रभाव और उससे होने वाले नुकसान को लेकर अभी भ्रम की स्थिति है।

पूंजी बाजार नियामक पर भी बाजार बंद करने का दबाव होगा। इससे चीजें और जटिल होंगी। अभी हालात ऐसे नहीं है कि दुनिया के एक हिस्से में कुछ संस्थान बंद हों। बल्कि दुनिया भर के तमाम शहर और राज्य बंद हो चुके हैं। भारत भी इससे अलग नहीं है।

तमाम जगहों पर शेयर कीमतें धराशायी हो रही हैं और बैंकों तथा कर्जदारों के लिए प्रतिभूति के लिए रखे गए शेयर बेमोल हो जाएंगे। यदि उन्होंने प्रतिभूति बेची तो उन्हें दिए गए कर्ज की तुलना में बहुत कम राशि मिलेगी और इसका कर्जदारों पर बहुत ही बुरा असर होगा। वित्तीय बाजारों को बंद करने के बजाय वित्तीय नियामकों को चाहिए कि वे मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए अधिकार प्रवर्तन और दायित्वों को फिलहाल पूरी तरह स्थगित कर दें। कंपनियों से कहा जा रहा है कि वे बोर्ड बैठकों का आयोजन न करें लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। जरूरत एक ऐसा ढांचा मुहैया कराने की हैजो कंपनियों को साहसी कदम उठाने में सक्षम बनाए और वे अगले तीन वर्ष के बारे में सोच सकें। पूरा का पूरा कानूनी ढांचा स्वस्थ वृद्धि को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसे तेजड़िया बाजार नियमन भी कहा जा सकता है। कानून तैयार करते वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि बाजार अनुमानों को कभी ऐसी दीर्घकालिक मंदी से गुजरना होगा। अब दोबारा विचार करने का वक्त आ गया है। विधायिका को भी कुछ वैसा ही हस्तक्षेप करना होगा जैसा न्यायपालिका ने समय सीमा बढ़ाकर किया। जैसा कि मेरे एक निजी इक्विटी निवेशक मित्र ने कहा, 'अब शल्य चिकित्सा का वक्त है, होमियोपैथी या किसी अन्य चिकित्सा से काम नहीं चलेगा।' जब हालात जंग जैसे आपातकालीन हों तो सोच में भी बदलाव लाना होता है, उस वक्त शांतिकालीन नीतिगत ढांचा काम नहीं आता है।

कानाफूसी

अनमोल तोहफा

जो भी लोग इस विषय में जानने की इच्छा रखते हैं, हम उन्हें बता दें कि यह साल का वह मौसम चल रहा है जब सामान्य दिनों में विभिन्न दलों के राजनेताओं की ओर से पार्टियों का आयोजन किया जाता है। बहरहाल, इस साल यह सिलसिला शुरुआत में ही थम गया। इस वर्ष किसी राजनेता द्वारा पत्रकारों को दी गई आखिरी पार्टी गत 13 मार्च को आयोजित की गई थी और इस पार्टी के मेजबान थे राज्य सभा सदस्य अभिषेक सिंघवी। हर वर्ष ऐसी पार्टियों का आयोजन आमतौर पर बसंत के मौसम में किया जाता है और ऐसी पहली पार्टियों की शुरुआत प्राय: बादल परिवार द्वारा दिए गए दोपहर भोज के साथ होती है। सिंघवी के पहले कांग्रेस के ही एक अन्य राज्य सभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की ओर से पार्टी का आयोजन किया गया था। उस पार्टी में उनकी बहू ने उन्हें जो तोहफा दिया था, आज उसकी सबसे अधिक मांग है। दरअसल उनकी बहू ने उन्हें हैंड सैनिटाइजर की एक छोटी बोतल तोहफे में दी थी।

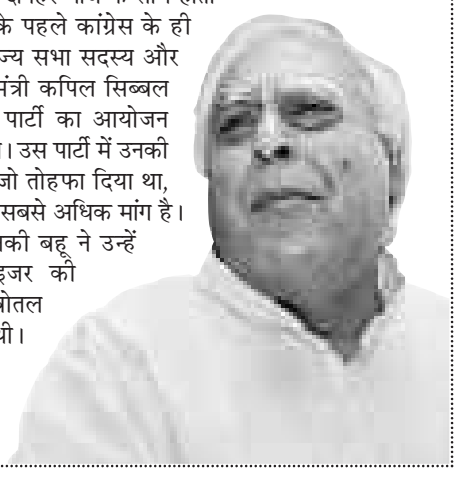

आपका पक्ष

राजनेता निभाएं अपनी जिम्मेदारी

कोरोना से बचने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इसे सफल बनाने के लिए सभी सत्ताधारियों-राजनेताओं और आम लोगों की भागीदारी जरूरी है। लेकिन अफसोस जिस देश में लोग राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, वहां सभी राजनेता संकट के समय जनता की सेवा के लिए आगे आएंगे ऐसा नामुमकिन लगता है। कोरोना के संकट के समय कुछ राजनेता लापता हो गए हैं। इनमें से बहुत से नेता आम लोगों की खैर खबर नहीं ले रहे हैं। ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे दुख की घड़ी में आम जनता की मदद करेंगे। अगर राजनेता अपने-अपने क्षेत्र के लोगों को इनके घर तक जरूरी सामान पहुंचाने की कोशिश करें, गरीब-मजदूरों की मदद करें तो लोग 21 दिन के लॉकडाउन के समय घर से बाहर नहीं निकलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हर राज्य के मुख्यमंत्री लोगों को हर मदद करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन इनके प्रयास तभी सफल होंगे, जब स्थानीय राजनेता भी इसके लिए गंभीरता दिखाएंगे।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

जैविक शस्त्र मानवता के लिए खतरा

लॉकडाउन सफल बनाने तथा लोगों की परेशानी करने के लिए विधायकों को अपने क्षेत्रवासियों की मदद करनी चाहिए

जब से कोरोना महामारी के रूप में देशों में फैला है अमेरिका तथा चीन के बीच तनाव देखने को मिला। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया कि कोरोना को चीन द्वारा जैविक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। आधुनिक काल में पहली बार जैविक हथियार का प्रयोग जर्मन सैनिकों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) में एंथ्रेक्स तथा ग्लैंडर्स के जीवाणुओं द्वारा किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार प्रकृति में ऐसे 200 प्रकार के बैक्टीरिया, विषाणु तथा फंगस मौजूद हैं जिससे जैविक शस्त्र बनाए जा सकते हैं। इस समय सभी देशों को आपसी संघर्षों को पीछे छोड़ कर शांति के मार्ग को अपनाना चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

अफवाहें न फैलाएं

भारत में करीब 60 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते हैं। बीते कुछ दिनों में देखा गया है कि लोग किसी भी सूचना को शेयर और फॉरवर्ड कर देते हैं जिनमें कुछ सूचनाएं गलत होती हैं। हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री की रोती हुई तस्वीर वायरल हुई और बताया कि प्रधानमंत्री कोरोना से अपने देश में हुई मौतों को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाए जबकि वह ब्राजील के राष्ट्रपति थे और वह तस्वीर काफी पुरानी थी। इस तरह की ऐसी तमाम अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। किसी भी सूचना को शेयर करने से पहले उसकी प्रमाणिकता जानना बहुत ही आवश्यक है अन्यथा इसका परिणाम भयावह हो सकता है।

हर्षवर्धन सिंह चौहान, रायबरेली

पानी की गहराती समस्या

देश के कई राज्यों में पानी की कमी की समस्या है। महाराष्ट्र के लातूर तथा राजस्थान में पीने के पानी की किल्लत के साथ वहां अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है। फसलों के उचित दाम नहीं मिल पाने तथा गरीबी व कर्ज के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या कर लेते हैं। देश के सभी नागरिकों को पानी का न्यूनतम उपयोग करना चाहिए ताकि वे आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचा सके। जल की समस्या हर साल बढ़ती जा रही है। आमतौर पर जो चीजें हमें मुफ्त में मिलती है हम उसका दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। प्रकृति ने हमें पीने के लिए मुफ्त में पानी दिया है जिसका व्यक्तिगत स्तर पर सभी नागरिक संरक्षण करें व दूषित होने से बचाएं। हर साल भारत के दक्षिण पूर्वी इलाकों में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। इस समय वाटर हार्वेस्टिंग से उस पानी का प्रयोग भूजल स्तर में सुधार के लिए किया जा सकता है।

हर्षवर्धन सिंह, रायबरेली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

एनएसई डेरिवेटिव में एफआईआई निवेश

	Week ended Mar 27		Week ended Apr 3	
	Contract (Nos)	Tovr (₹bn)	Contract (Nos)	Tovr (₹bn)
Index Future	1498659	802.5	657341	349.8
Stock Future	5028354	2153.2	1454415	648.8
Index Option	17682209	9413.4	13767305	6768.9
Stock Option	130224	65.9	65257	34.5
Total	24339446	12435.0	15944318	7848.9

बीएसई 500 कंपनियों में एफआईआई शेयरधारिता

IN %	DEC '18	MAR '18	JUN '19	SEP '19	DEC '19
Cummins India	11.8	9.6	9.5	8.8	6.8
Dalmia Bhara.	0.9	17.4	16.7	15.9	14.8
Edelweiss.Fin.	31.4	31.4	32.5	32.3	32.8
Emami	11.0	11.6	12.2	12.1	10.8
Endurance Tech.	10.1	15.8	16.4	17.0	16.9
Engineers India	6.9	7.0	7.0	8.2	9.1
Escorts	21.7	24.6	21.1	21.8	20.4
Exide Inds.	12.5	10.4	9.4	9.6	9.4
Federal Bank	39.7	39.5	39.8	36.9	33.6
Fortis Health.	39.2	40.3	39.3	39.3	43.7
Future Consumer	27.4	27.9	28.1	28.2	28.4
Future Retail	15.0	13.6	13.8	13.0	12.7
Glenmark Pharma.	32.9	33.2	31.7	32.3	31.0
GMR Infra.	19.8	18.6	18.8	21.6	21.5
Godrej Agrovet	16.1	16.2	16.4	16.6	16.5
Godrej Inds.	11.9	12.1	11.9	11.9	12.0
Godrej Propert.	14.4	14.3	20.7	20.7	19.6
Graphite India	9.3	8.2	8.8	10.7	11.2
Guj.St.Petronet	17.6	17.1	16.0	16.1	16.3
HUDCO	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
HEG	8.4	6.3	7.3	7.8	10.7
Hexaware Tech.	18.1	17.0	17.7	18.8	17.9
IDBI Bank	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0

एफआईआई/डीआईआई निवेश

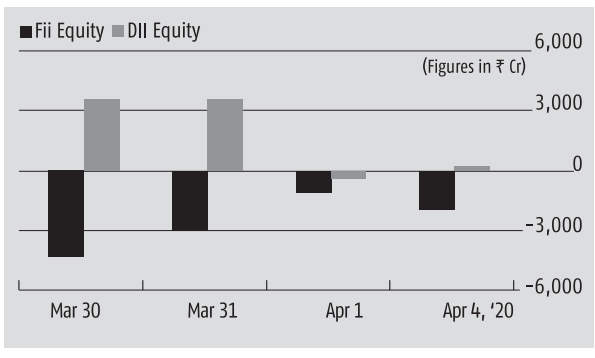

सप्ताह का शेयर (जिंदल स्टील ऐंड पावर)

Stock hit 3 years and 10 months low today at ₹ 62.10, down 29 per cent in one week

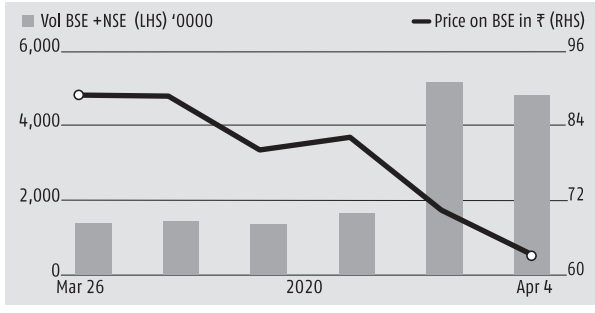

निफ्टी स्नैपशॉट

	Mar 27	Mar 30	Mar 31	Apr 1	Apr 3
Nifty 50 Spot	8660.3	8281.1	8597.8	8253.8	8083.8
Nifty 50 Future	8651.4	8290.2	8621.0	8257.3	8084.5
Prem/Discount	-8.8	9.1	23.2	3.5	0.7
Fut(Open Int)	11308	11970	11721	11010	10934
Fut(Contract)	355908	289865	301141	273292	263362
Fut(Value ₹ Cr)	23368.1	18372.6	19317.9	17052.4	16054.8
PCR(Open Int)	1.3	1.1	1.2	1.0	1.1
PCR(Contract)	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
Major Call(Strike Price)	10000.0	10000.0	9000.0	8300.0	9000.0
Major Call(LTP)	18.1	2.9	14.8	1.4	117.6
Major Put(Strike Price)	7500.0	8000.0	8000.0	8000.0	8000.0
Major Put(LTP)	345.5	566.4	390.6	450.4	441.4

पुट/कॉल रेशियो

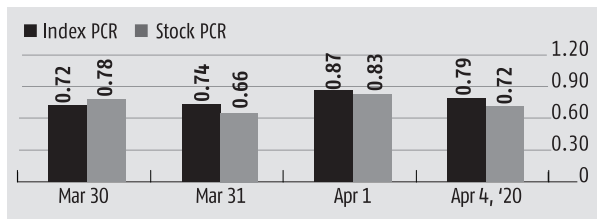

सेक्टर पर नजर

TOP GAINERS	OI '000	% chg	TOP LOSERS	OI '000	% chg
Pharmaceutical	324	63.4	IT - Software	114997	17.5
Fertilizers	992	38.6	Consumer Durables	30106	16.6
Steel	120770	33.0	Chemicals	2530	16.5
Packaging	1521	30.6	Gas Distribution	45469	15.2
Refineries	135717	20.9	Plantation & Plantation	8934	15.1
Miscellaneous	13059	20.6	**TOP LOSERS**		
Castings, Forgings	6477	19.2	Telecom	6632	-6.9
Automobile	162189	18.8	Infrastructure Developers	98710	
Banks	772056	18.7	-3.1		
Construction	20403	18.0	Diversified	24171	-2.4

कीमत में बढ़ोतरी के साथ ओपन इंटरेस्ट

	Open Int as on			Price as on		
	Mar 27	Apr 03	% Chg	Mar 27	Apr 03	% Chg
Torrent Phar	196000	312000	59.2	1860.2	2077.0	11.7
Biocon	4882900	7564700	54.9	277.7	291.0	4.8
HPCL	809970	10754100	32.8	170.3	184.2	8.2
Cadila Healt	2398000	2994200	24.9	252.7	274.6	8.7
Lupin	5124700	6284600	22.6	548.1	655.9	19.7
Divis Lab	1758000	2126400	21.0	1862.6	1901.1	2.1
Dr Reddys	1934250	2321250	20.0	2916.5	3146.8	7.9
Reliance Ind	3410050	40319000	18.2	1065.6	1077.5	1.1
IOC	4262800	49644000	16.5	76.9	79.5	3.4
Amara Raja	837600	953600	13.8	455.4	460.2	1.1
CESC	1396800	1206400	-13.6	389.4	425.6	9.3
Indraprst Gs	3509000	3935250	12.1	357.4	406.7	13.8
Petronet LNG	910200	10188000	11.9	193.5	195.8	1.2
Torrent Pwer	1533000	1368000	-10.8	271.9	279.0	2.6
Rural Elect	1954800	021306000	9.0	85.0	85.1	0.1
Godrej Cons	6048000	6544800	8.2	499.5	531.5	6.4
ACC	1998000	1854800	-7.2	959.2	962.6	0.4
Century Tex	2056800	1915800	-6.9	282.4	286.1	1.3

एनएसई सूचकांक

	Mar 27	Apr 3	% Chg
SPOTNifty 50	8660.3	8083.8	-6.7
Bank Nifty	19969.0	17249.3	-13.6
Nifty IT	12569.1	11680.0	-7.1
Futures (LTP)			
Nifty 50	8651.4	8084.5	-6.6
Bank Nifty	19778.7	17175.8	-13.2
Nifty IT	12408.0	11710.0	-5.6
Open Interest			
Nifty 50	11307525.0	10933875.0	-3.3
Bank Nifty	983040.0	1050660.0	6.9
Nifty IT	950.0	850.0	-10.5

तेजी/गिरावट (बीएसई)

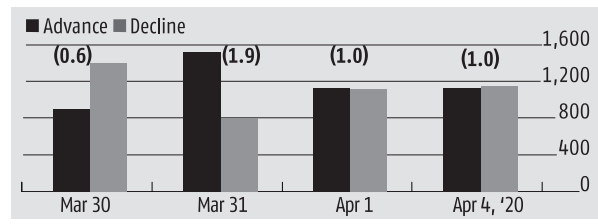

मार्केट पोजीशन

HIGHEST	OI	% of MWL	LOWEST	OI	% of MWL
Adani Enter	16580000	30.05	Ramco Cements	426400	1.58
Sun Pharma	61738750	28.31	United Brew	417200	1.87
Jindal Steel	22225000	27.79	MRF	12610	2.06
Adani Power	52080000	26.98	Tata Chem	991800	2.82
Grasim Ind	20844000	26.55	Voltas	1381000	2.99
Sesa Sterlite	96649000	26.28	Torrent Pwer	1419000	3.18
PNB	56689000	25.03	Torrent Phar	323500	3.32
DLF	30343500	24.47	Cummins (I)	929700	3.42
Yes Bank	108389600	23.18	Bharti Infratel	6632000	3.86

कीमत में गिरावट के साथ ओपन इंटरेस्ट

	Open Int as on			Price as on		
	Mar 27	Apr 03	% Chg	Mar 27	Apr 03	% Chg
Jindal Steel	501500	16820000	235.4	88.9	63.2	-28.9
Godrej Prpty	11700	38350	227.8	690.5	608.1	-11.9
Cummins (I)	443700	901800	103.2	357.6	298.7	-16.5
RBL Bank	881550	013591500	54.2	160.3	111.0	-30.8
Chola Inv	2762500	3842500	39.1	169.2	124.7	-26.3
Tata Chem	692100	930600	34.5	224.5	218.6	-2.7
Bosch	89360	119360	33.6	9931.5	8816.7	-11.2
L&T Finance Hol	1337840	016906400	26.4	53.1	48.9	-7.9
Maruti Suzuki	2012500	2520000	25.2	4646.1	4011.5	-13.7
Escorts	2247300	1703900	-24.2	654.8	592.4	-9.5
Max India	1131000	1400100	23.8	408.5	333.9	-18.3
Bajaj Finsrv	548875	664875	21.1	4890.6	4510.8	-7.8
HDFC Std Life	874350	010581300	21.0	441.0	422.3	-4.2
Infosys	3002640	036291600	20.9	652.7	585.7	-10.3
Eicher Motor	183120	220050	20.2	14319.8	12680.1	-11.5
Yes Bank	4980800	059787200	20.0	26.4	24.1	-8.5
MRF	15610	12590	-19.3	56371.3	55062.3	-2.3
PVR	695200	827200	19.0	1257.2	1007.0	-19.9

बीएसई सूचकांक

	Mar 27	Apr 03	Change	% Chg
Sensex	**29815.6**	**27590.9**	**-2224.6**	**-7.5**
OUTPERFORM SENSEX				
Oil & Gas	9339.8	10007.2	667.4	7.1
Healthcare	11628.8	12395.0	766.2	6.6
FMCG	9632.7	9982.0	349.3	3.6
PSU	4295.8	4284.0	-11.8	-0.3
Smallcap	9497.2	9409.0	-88.2	-0.9
Metal	5604.5	5466.4	-138.1	-2.5
Midcap	10537.9	10219.0	-318.8	-3.0
Cons Durable	19475.5	18770.0	-705.4	-3.6
BSE-500	11106.5	10527.3	-579.2	-5.2
BSE-200	3613.5	3415.7	-197.8	-5.5
Cap. Goods	11200.5	10584.3	-616.1	-5.5
BSE-100	8692.8	8179.9	-512.9	-5.9
Dollex-200	798.3	747.0	-51.2	-6.4
Dollex-100	1193.2	1111.6	-81.6	-6.8
UNDERPERFORM SENSEX				
Bankex	22965.5	19753.8	-3211.7	-14.0
Auto	11223.8	10269.5	-954.3	-8.5
Dollex-30	3248.0	2975.6	-272.4	-8.4
IT	12791.1	11780.9	-1010.2	-7.9
TECk	6401.4	5914.4	-487.0	-7.6

मार्केट एग्रीगेट्स

	WEEK END			WEEK END	
BSE	Mar 27	Apr 3	NSE	Mar 27	Apr 3
Shares(In Lakhs)	12777	6569	Shares(In Lakhs)	106134	69300
Turnover(In Crore)	35378	8160	Turnover(In crore)	211824	146776
Traded(000)	9193	6158	Traded(000)	104981	71246

डिलिवरी

	BSE		NSE	
DATE	Trd. shares (bn)	% Delivery	Trd. shares (bn)	% Delivery
Apr 03, 2020	1510.9	54.0	18238.2	38.1
Apr 01, 2020	1420.9	46.3	15664.0	36.1
Mar 31, 2020	2002.2	63.3	19034.9	40.6
Mar 30, 2020	1671.4	55.0	15796.8	40.2
Mar 27, 2020	3643.4	70.9	22676.8	38.0
Mar 26, 2020	2616.9	58.0	24306.2	42.1
Mar 25, 2020	3066.1	75.2	18770.7	43.5
Mar 24, 2020	1799.1	43.8	20531.2	41.9
Mar 23, 2020	1771.4	53.0	19216.9	53.8

शेयर सूचकांकों में उतार-चढ़ाव

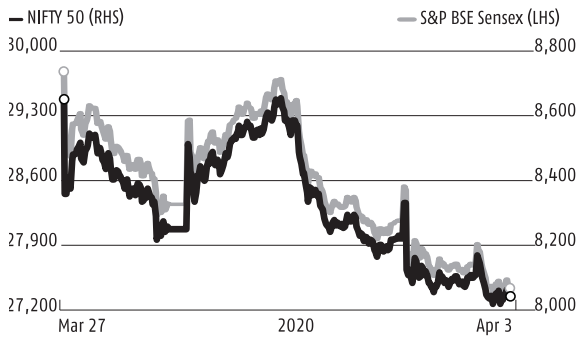

बीएसई 500

	Mar 27	Apr4, '20	% chg
मुनाफे में			
KRBL	112.70	157.35	39.62
Himadri Specialt	30.50	42.00	37.70
PC Jeweller	9.55	12.72	33.19
Balrampur Chini	90.00	114.55	27.28
Infibeam Avenues	32.05	40.60	26.68
Sobha	130.95	160.20	22.34
Edelweiss.Fin.	34.65	42.05	21.36
Intellect Design	49.65	60.25	21.35
Delta Corp	59.50	72.15	21.26
Reliance Infra.	9.20	11.13	20.98
Dishman Carbogen	48.85	59.05	20.88
Guj Alkalies	210.85	253.00	19.99
Rail Vikas	12.80	15.35	19.92
Lupin	547.00	654.80	19.71
Reliance Power	1.13	1.34	18.58
Graphite India	118.15	140.10	18.58
GHCL	80.55	95.30	18.31
Suzlon Energy	1.87	2.20	17.65
Proc. Gam. Heal.	3,292.15	3,864.65	17.39
Centrum Capital	8.55	9.95	16.37
GAIL (India)	69.50	80.85	16.33
KEI Inds.	255.20	295.15	15.65
Emami	158.70	182.35	14.90
Zensar Tech.	77.05	88.50	14.86
Advance. Enzyme.	115.60	131.65	13.88
B P C L	278.90	317.20	13.73
Jindal Saw	41.60	47.30	13.70
Indraprastha Gas	358.45	406.60	13.43
Finolex Cables	191.70	217.10	13.25
G S F C	34.75	39.35	13.24
Oracle Fin.Serv.	1,800.95	2,039.25	13.23
Mahindra CIE	64.20	72.50	12.93
Heritage Foods	200.45	226.00	12.75
Phillips Carbon	61.45	69.25	12.69
Syngene Intl.	223.10	251.40	12.68
Vaibhav Global	716.70	806.00	12.46
Narayana Hrudaya	237.35	266.55	12.30
घाटे में			
Ircon Intl.	373.65	90.30	-75.83
RBL Bank	160.40	110.95	-30.83
Jindal Steel	88.80	63.20	-28.83
Shriram Trans.	724.45	520.90	-28.10
Bandhan Bank	250.25	181.60	-27.43
Cholaman.Inv.&Fn	168.65	124.65	-26.09
IndusInd Bank	411.00	313.25	-23.78
Chola Financial	339.50	268.30	-20.97
PVR	1,257.25	1,010.00	-19.67
Capri Global	174.90	142.00	-18.81
Kotak Mah. Bank	1,397.95	1,140.00	-18.45
Future Lifestyle	130.60	106.55	-18.42
Future Retail	87.20	71.15	-18.41
Future Consumer	7.75	6.33	-18.32
Indiabulls Integ	47.30	38.65	-18.29
Sadbhav Engg.	31.30	25.60	-18.21
Max Financial	406.95	335.10	-17.66
Va Tech Wabag	91.65	75.50	-17.62
TVS Motor Co.	304.20	252.85	-16.88
Cummins India	359.60	298.90	-16.88
Bharat Forge	263.30	219.55	-16.62
Ujjivan Fin.Ser.	169.90	142.45	-16.16
Repco Home Fin	129.75	109.05	-15.95
Dalmia Bhara.	502.75	423.00	-15.86
ICICI Bank	340.10	286.50	-15.76
J & K Bank	13.30	11.21	-15.71
Mindtree	828.75	700.40	-15.49
Ashoka Buildcon	44.00	37.45	-14.89
H D F C	1,754.10	1,499.40	-14.52
K E C Intl.	187.60	160.50	-14.45
Equitas Holdings	43.35	37.20	-14.19
Can Fin Homes	305.10	262.20	-14.06
CreditAcc. Gram.	374.45	321.80	-14.06
Shoppers St.	222.25	191.55	-13.81

सेक्टर सूचकांक

Return (%)	Apr 3, '20	1 week	1 month	3 month	6 month	1 year
BSE Sensex	27,590.95	-7.5	-28.6	-33.5	-27.6	-29.0
S&P CNX Nifty	8,083.80	-6.7	-28.5	-33.9	-28.6	-30.6
BSE-100	8,179.94	-5.9	-28.4	-33.5	-28.4	-30.8
BSE-200	3,415.68	-5.5	-28.4	-33.1	-27.7	-30.5
BSE-500	10,527.29	-5.2	-28.8	-33.3	-27.8	-31.3
CNX Midcap	11,316.75	-3.8	-33.4	-34.6	-28.0	-37.6
CNX Nifty Junior	20,399.70	-0.2	-24.2	-28.4	-24.5	-27.2
S&P CNX 500	6,638.45	-5.2	-28.8	-33.2	-27.8	-31.3
BSE-Auto	10,269.50	-8.5	-34.8	-43.9	-38.7	-46.4
BSE-Bankex	19,753.84	-14.0	-41.1	-45.9	-38.4	-41.6
BSE-Cap. Goods	10,584.34	-5.5	-31.7	-38.9	-42.5	-42.6
BSE-Cons Durable	18,770.03	-3.6	-28.4	-23.7	-27.8	-20.1
BSE-FMCG	9,982.00	3.6	-9.3	-12.7	-14.5	-14.3
BSE-Healthcare	12,394.97	6.6	-11.0	-8.7	0.4	-12.9
BSE-IT Sector	11,780.88	-7.9	-23.2	-25.3	-23.3	-24.6
BSE-TECk	5,914.44	-7.6	-22.9	-24.4	-20.8	-23.7
BSE Realty	1,321.32	-7.4	-38.8	-42.3	-31.3	-37.3
BSE-Metal	5,466.39	-2.5	-35.9	-48.4	-36.9	-52.6
BSE-Oil & Gas	10,007.20	7.1	-21.5	-32.5	-32.9	-32.7
BSE-PSU	4,284.00	-0.3	-27.5	-38.8	-35.2	-43.3

वैश्विक सूचकांक*

Return (%)	Apr 3, '20	1 week	1 month	3 month	6 month	1 year
FTSE 100	5,415.50	-1.7	-19.4	-29.0	-23.5	-27.0
Nikkei 255	17,820.20	-8.1	-15.5	-24.7	-16.5	-17.9
Hang Seng	23,236.10	-1.1	-11.6	-18.3	-11.0	-22.5
Nasdaq	7,373.10	-1.7	-15.1	-18.3	-6.3	-6.6
Dow Jones	21,052.50	-2.7	-18.8	-26.5	-19.7	-19.7
₹/$	76.2	-1.7	-3.8	-5.7	-6.9	-10.2
Brent Crude (spot)$/Bbl	28.0	14.0	-45.8	-59.4	-51.7	-59.5

मोटा सौदा

Date	Stock	Client	Type	Quantity	Price (₹)
Mar 30	Teamlease Services	Enam Investment Services	SELL	99152	1495.00
Mar 31	Multi Commodity Exchange	East Bridge Capital Master Fund	SELL	906409	1066.08
Mar 31	Multi Commodity Exchange	Ward Ferry Mgt. A/C Wf Asian Smaller Cos	BUY	902482	1066.00
Mar 30	HDFC Bank	Theleme Master Fund	BUY	3107852	901.00
Mar 30	HDFC Bank	Morgan Stanley Asia (Singapore)	SELL	3107852	901.00
Mar 30	Kalyani Invest Co	Morgan Stanley Asia (Singapore)	BUY	93000	865.05
Mar 30	Kalyani Invest Co	Metrica Asia Event Driven Master	SELL	93000	865.05
Mar 30	Nalwa Sons Investments	Morgan Stanley Asia (Singapore)	BUY	53000	475.05
Mar 30	Nalwa Sons Investments	Metrica Asia Event Driven Master	SELL	53000	475.05
Mar 30	Rajpalaym Mills	Morgan Stanley Asia (Singapore)	BUY	87000	458.05
Mar 30	Rajpalaym Mills	Metrica Asia Event Driven Master	SELL	87000	458.05
Mar 31	Bharti Airtel	Blackrock Global Funds India Fund	BUY	300000	441.00
Mar 31	Bharti Airtel	Merrill Lynch India Equities Fund (Mauritius)	SELL	300000	441.00
Apr 03	EMBASSY Office Parks REIT	American Balanced Fund	BUY	9514600	321.50
Mar 31	Apollo Pipes	Canara Hsbc Orient Bk Of Comm Life Ins	SELL	98989	242.00
Mar 30	Summit Securities	Morgan Stanley Asia (Singapore)	BUY	105000	233.50
Mar 30	Summit Securities	Metrica Asia Event Driven Master	SELL	105000	233.50
Apr 01	Paisalo Digital	Antara India Evergreen Fund	BUY	264937	159.00
Apr 01	Paisalo Digital	Davos International Fund	SELL	265000	159.00
Mar 31	Suprajit Engineering	Hdfc Mutual Fund (Hdfc Small And Mid Cap Fund)	BUY	3000000	113.50
Mar 31	Suprajit Engineering Limi	National Westminster Bank Plc	SELL	2500932	113.50
Mar 30	GHCL	J. P. Financial Services	SELL	480000	83.28
Mar 31	Delta Corp	Derive Investments	SELL	1550000	65.25
Mar 30	Asian Hotels (North)	Venus India Asset-Finance Private	SELL	270000	64.95
Apr 03	Shalby	Goldman Sachs India Fund	SELL	1231536	43.04
Apr 03	Shalby	Goldman Sachs India Fund	SELL	1300000	43.03
Apr 03	Indiabulls Integr Ser	Toscafund Asset Management LLP A/C Tosca	BUY	815000	40.70
Apr 03	Indiabulls Integr Ser	Toscafund Asset Management LLP A/C Tosca	SELL	815000	40.70
Mar 30	Aartech Solonics	Fortune Futures Private Co	SELL	132000	34.50
Mar 30	Genesys International	Pivotal Business Managers LLP	BUY	430000	21.10
Mar 30	Rajnish Wellness	Pivotal Business Managers LLP	BUY	211200	18.65
Mar 30	Cerebra Intgrated Tech	Societe Generale	SELL	845897	18.50
Mar 31	NCC	Kbc Eco Fund	BUY	4021825	17.87
Mar 31	NCC	Tower Research Capital Markets India	SELL	3474760	17.60
Mar 31	NCC	Tower Research Capital Markets India	BUY	3357052	17.54
Mar 30	Jain Irrigation Systems	Avtar Instalments Private	BUY	2886517	3.23
Mar 31	Lancor Holdings	Securities Research & Analysis	BUY	797500	3.11

ओपन इंटरेस्ट ब्रेक अप

	Price as on April 3, '20		Open interest		% of Open interest		
	Close (cash)	LTP (future)	Shares	₹ crore	Futures	Call	Put
Adani Ports	244.8	245.9	27070	662.7	97.8	1.3	0.8
Asian Paints	1520.9	1523.2	6338	964.0	90.6	5.5	3.9
Axis Bank	325.5	327.0	58734	1911.5	87.3	8.1	4.6
Bajaj Auto	2033.8	2042.7	1464	297.6	92.1	4.0	3.9
Bajaj Fin	2207.5	2217.9	6294	1389.5	73.5	14.2	12.3
Bajaj Finsrv	4510.8	4509.4	697	314.6	95.3	4.0	0.7
Bharti Airtel	424.0	425.0	59421	2519.1	94.4	4.2	1.4
Bharti Infratel	156.4	157.1	6632	103.7	97.2	1.2	1.5
BPCL	317.2	316.9	20426	647.8	86.0	8.2	5.7
Britannia	2563.3	2570.9	1131	290.0	94.7	3.9	1.4
Cipla	449.2	449.4	12386	556.4	76.2	17.1	6.7
Coal India	137.8	137.9	27327	376.4	86.1	7.8	6.1
Dr Reddys	3146.8	3158.0	2511	790.1	92.5	4.8	2.7
Eicher Motor	12680.1	12657.6	228	289.7	96.3	2.0	1.7
GAIL	80.9	81.2	28905	233.8	86.1	8.1	5.8
Grasim Ind	454.7	456.6	20844	947.8	99.0	0.7	0.3
HCL Techno	405.8	406.0	22999	933.3	96.9	1.0	2.1
HDFC	1499.6	1506.4	29417	4411.3	96.0	2.7	1.3
HDFC Bank	813.9	808.2	31879	2594.4	84.6	9.9	5.5
Hero MotoCorp	1582.1	1589.1	2341	370.4	85.7	6.7	7.6
Hindalco	88.8	89.1	38794	344.5	88.6	7.3	4.1
HUL	2154.1	2158.8	10424	2245.5	87.5	8.3	4.2
ICICI Bank	286.7	286.0	96509	2766.4	85.9	9.2	4.9
IndusInd Bank	313.2	313.8	22352	700.1	76.4	13.5	10.0
Infosys	585.7	587.1	40978	2400.1	88.6	6.6	4.8
IOC	79.5	79.7	54980	437.1	90.3	7.0	2.8
ITC	177.9	177.8	96686	1720.1	76.7	12.3	11.0
JSW Steel	140.7	139.8	35949	505.8	94.9	2.4	2.7
Kotak Mah Bank	1140.9	1144.2	11427	1303.6	80.5	12.1	7.4
L & T	774.7	779.8	12989	1006.2	88.5	7.1	4.4
Mah & Mah	280.7	282.0	16568	465.1	93.9	3.2	2.9
Maruti Suzuki	4011.5	4006.1	3083	1236.9	81.7	13.0	5.3
Nestle India	15104.7	15146.7	378	571.4	95.3	3.6	1.2
NTPC	79.6	80.1	44899	357.2	95.1	3.8	1.1
ONGC	69.9	70.1	69101	482.7	80.3	11.8	7.8
Power Grid	156.2	156.9	40084	626.1	97.2	2.1	0.8
Reliance Ind	1077.5	1080.4	48148	5187.7	83.7	9.3	7.0
SBI	175.5	175.4	142461	2500.2	59.4	25.9	14.7
Sesa Sterlite	62.8	63.2	96649	607.0	89.6	7.4	2.9
Shree Cement	15783.8	15716.3	141	222.2	99.9	-	0.1
Sun Pharma	376.0	376.0	61739	2321.1	86.7	7.7	5.6
Tata Motors	65.3	65.1	75370	492.2	69.0	19.3	11.7
Tata Steel	253.8	251.3	22467	570.1	63.8	22.2	14.0
TCS	1654.2	1656.8	17317	2864.5	88.4	5.4	6.2
Tech Mahindra	520.9	522.5	12461	649.1	97.0	1.5	1.5
Titan Company	862.8	865.8	6559	565.9	88.2	7.7	4.1
UltraTech	3041.6	3041.1	1905	579.3	98.2	1.1	0.7
UPL	298.1	297.8	12844	382.9	97.7	1.3	1.0
Wipro	180.0	180.8	20096	361.7	95.2	3.7	1.1
Zee Enter	124.4	124.1	21080	262.1	89.9	7.2	2.9

चाय कंपनियों को सता रहा वित्तीय संकट

लॉकडाउन के कारण आमदनी नहीं हो रही, लेकिन मजदूरी और कर्ज अदायगी जैसी तय लागत में हो रही बढ़ोतरी

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 5 अप्रैल

चाय कंपनियां गहराते वित्तीय संकट को लेकर चिंतित हैं। उन्हें इस साल करीब आठ करोड़ किलोग्राम चाय उत्पादन का नुकसान होने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने चाय कंपनियों को लॉकडाउन के बीच फिर से चाय उत्पादन शुरू करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात कंपनियों को परिचालन फिर से शुरू करने की मंजूरी दी। हालांकि उन्हें किसी भी समय आधे कामगारों के साथ परिचालन करना होगा। अब संबंधित राज्य सरकारों और जिलाधीशों को यह आदेश जारी करना होगा और आगे के दिशा-निर्देश जारी करने होंगे।

एक बागान कंपनी के प्रवर्तक ने कहा, 'उत्पादन रुके होने और परिवहन सेवाएं उपलब्ध न होने के कारण कोई आमदनी नहीं हो रही। दूसरी ओर पारिश्रमिक, कर्ज अदायगी, ब्याज जैसी निश्चित लागतों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इससे वित्तीय असंतुलन और बिगड़ेगा, जिससे चाय कंपनियां पहले ही जूझ रही हैं।'

उद्योग के सूत्रों ने आरोप लगाया कि इस उद्योग को कई वर्षों से कर्ज मिलना कम हो गया है। ज्यादातर चाय बागान कंपनियां या तो घाटे में हैं या उनके लाभ में तेजी से गिरावट आ रही है।

उदाहरण के लिए वारेन टी का शुद्ध लाभ 2013-14 में 20.24 करोड़ रुपये था, जबकि कंपनी 2018-19 में 15.92 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही थी।

बागान उद्योग

- केंद्र ने चाय बागान कंपनियों को फिर से परिचालन शुरू करने की मंजूरी दी
- किसी भी समय 50 फीसदी कामगारों का ही किया जा सकता है इस्तेमाल
- चाय पत्ती तुड़ाई के पहले सीजन में चाय कंपनियों को 8 करोड़ किलोग्राम चाय का नुकसान होने की आशंका
- दूसरे सीजन में सामान्य स्तर का 70 फीसदी उत्पादन होने का अनुमान

गुडरिक समूह को कैलेंडर वर्ष 2014 में 22.24 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था, लेकिन यह 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में घटकर 9.49 करोड़ रुपये पर आ गया। रोसेल इंडिया को भी 2013-14 में 20.40 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था, जो पिछले वित्त वर्ष में घटकर 0.57 करोड़ रुपये पर आ गया।

उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, 'चाय पत्ती तोड़ने के पहले सीजन में उत्पादन के नुकसान से वित्तीय स्थिति और खराब होने के आसार हैं और हम यह भी नहीं जानते कि मौजूदा हालात में दूसरा सीजन भी कैसा रहेगा। हालांकि आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार कर्ज लौटाने में कुछ समय की मोहलत दी जा रही है, लेकिन हमें असर को समझना होगा और फिर कोई फैसला लेना होगा।' कंपनियां केंद्र की अधिसूचना में कामगारों की शर्त को लेकर भी चिंतित है, जिससे चाय तुड़ाई के अगले सीजन की शुरुआत में उत्पादन प्रभावित हो सकता है।

जय श्री टी ऐंड इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक और सीईओ डी पी माहेश्वरी ने कहा, 'सबसे अधिक उत्पादन की अवधि शुरू हो चुकी है, जिसमें हमें पूरी क्षमता पर परिचालन की जरूरत है। कम कामगारों के साथ परिचालन से निश्चित रूप से उत्पादन प्रभावित होगा।'

उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि हालांकि उत्पादन फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन चाय पत्ती तोड़ने का पहला सीजन लगभग पूरा हो चुका है। इसके चलते फसल के नुकसान का अनुमान बदलकर आठ करोड़ किलोग्राम कर दिया गया है, जो पहले 10 करोड़ किलोग्राम था। इसका मतलब है कि उद्योग को करीब 1,600 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, जिसका पहले 2,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था। चाय बागान मालिकों ने कहा कि मई से शुरू होने वाले पत्ती तुड़ाई के दूसरे सीजन की तैयारियां की जा सकती हैं, लेकिन वे उत्पादन को लेकर सुनिश्चित नहीं हैं। गुडरिक समूह के प्रबंध निदेशक अतुल अस्थाना ने कहा, 'बागानों के फिर से खुलने के बाद सबसे पहले स्कीफिंग करनी होगी और चाय उत्पादन शुरू होने से पहले इसमें 8-10 दिन लगेंगे।'

अधिकारियों ने कहा कि आदेश के समय को देखते हुए उत्पादन अप्रैल के मध्य से पहले शुरू नहीं हो सकता है। माहेश्वरी ने कहा, 'हम नहीं जानते कि कोविड-19 का प्रसार कितना होगा और दूसरा सीजन शुरू होने पर कैसी स्थितियां रहेंगी।' हालांकि बागान कंपनियों का मानना है कि दूसरे सीजन में आम उत्पादन का कम से कम 70 फीसदी उत्पादन संभव है, लेकिन वे मजदूरों की उपलब्धता और श्रम संगठनों के रुख को लेकर फिक्रमंद हैं। पूरे देश में दूसरे सीजन के दौरान करीब 23 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है, जो पूरे साल में उत्पादित होने वाली चाय का करीब 17 फीसदी है। यह चाय सबसे महंगी होती है और वर्ष के शेष सीजनों की तुलना में सबसे बेहतर गुणवत्ता की होती है।

चाय बोर्ड के चेयरमैन और बोकाहोला टी कंपनी के प्रबंध निदेशक पीके बेजबरुआ ने कहा, 'राज्य सरकारों को भी ऐसे ही आदेश जारी करने चाहिए। कामगारों को भी सहयोग देना चाहिए ताकि उत्पादन शुरू हो सके।'

विश्व में श्रमिकों के सबसे बड़े संगठन असम चाय मजदूर संघ (एसीएमएस) बागानों के प्रबंधकों के साथ सहयोग को तैयार है। हालांकि इस संगठन ने पहले बागानों को बंद करने की बात कही थी।

एसीएमएस के अध्यक्ष पवन सिंह घटोवार ने कहा, 'उत्पादन को 3-4 महीने और वह भी उत्पादन के प्रमुख सीजन में बंद करना अव्यावहारिक है। हम सभी की राय सुनने को तैयार हैं और राज्य प्रशासन और चाय बागानों के साथ सहयोग करेंगे बशर्ते कि कामगारों की उचित सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए।'

समुद्री खाद्य निर्यात में गिरावट

टीई नरसिम्हन और
जयजित दास
चेन्नई/भुवनेश्वर, 5 अप्रैल

वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप और प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य संकट में इसके बढ़ते असर ने उन भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों को चिंता में डाल दिया है जो प्रति वर्ष सात अरब डॉलर मूल्य का समुद्री खाद्य निर्यात करते हैं।

कोविड-19 का प्रकोप और इसके परिणामस्वरूप हुए लॉकडाउन के बाद से देश के सबसे बड़े समुद्री खाद्य बाजार अमेरिका को भेजी जाने वाली खेपों में 50 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। 2.8 लाख टन निर्यात के साथ भारत अमेरिका को झींगा निर्यात करने वाला सबसे बड़ा निर्यातक है। अमेरिका के आयात में इसकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत रहती है। एक प्रमुख निर्यातक ने कहा कि इसके अलावा यूरोपीय संघ, वियतनाम और जापान जैसे प्रमुख बाजारों से नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, जबकि स्पेन ने खरीद रोक दी है।

अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात 50 प्रतिशत फिसला

ओडिशा स्थित एक समुद्री खाद्य निर्यातक ने कहा, 'कोरोनावायरस के प्रकोप के बाद हमें निर्यात बाजार से नए ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं। समुद्री खाद्य निर्यातक पहले किए गए अनुबंध के ऑर्डर पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि पहले किए गए कुछ ऑर्डर रद्द भी किया जा रहे हैं क्योंकि यह महामारी फैलने से रोकने के लिए देशों में अधिक सावधानी बरती जा रही है।'

लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ओडिशा में समुद्री खाद्य उत्पादन रुक गया है क्योंकि राज्य के विभागों ने प्रसंस्करण संयंत्रों को परिचालन की अनुमति प्रदान नहीं की है। केवल कोल्ड स्टोरेज सुविधा केंद्रों को ही सामान्य रूप से कार्य करने की अनुमति है। इसके अलावा पर्याप्त श्रम बल की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन निष्क्रिय हो गया है। इससे यह अर्थ निकलता है कि केवल पहले से प्रसंस्कृत किए गए समुद्री उत्पादों के स्टॉक को ही विदेशों में भेजा जा सकता है। हालांकि खरीदार देशों के बीच कमजोर पड़ती मांग से निर्यातकों की भावना प्रभावित हुई है।

फाल्कन मरीन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड फ्रोजन और ताजा झींगा निर्यात करने वाली देश की सबसे बड़ी निर्यातक है जिसका कुल कारोबार 1,500 करोड़ रुपये से अधिक है। कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन तारा रंजन पटनायक का कहना है कि भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों के लिए यह बहुत बुरा साल रहने वाला है। दाम गिर रहे हैं क्योंकि निर्यात खत्म हो गया है। आयातक देशों के बीच मांग कम हो चुकी है। संकट के इस समय में निर्यात सुविधा के लिए भारत सरकार के प्रयासों के सामने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की बाधा आ गई है। खेप की ढुलाई के लिए ट्रक और श्रमिक उपलब्ध नहीं हैं। निर्यातकों को एमपीईडीए (समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) से प्रमाण-पत्र लेने जैसी कागजी कार्रवाई भी करनी पड़ती है।

भारत से किए जाने वाले कुल समुद्री खाद्य निर्यात में चीन की हिस्सेदारी तकरीबन 13 प्रतिशत है और वह तेजी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक है। एमपीईडीए के चेयरमैन केएस श्रीनिवास ने कहा कि चीन में सभी खरीदार चीन के नव वर्ष के कारण शीर्ष मांग की पूर्ति के लिए पहले ही अपने स्टॉक में अच्छा-खासा इजाफा कर लिया है और नए ऑर्डर आमतौर पर अवकाश अवधि के बाद दिए जाते हैं जो फरवरी के दूसरे सप्ताह तक चलते हैं। वायरस का प्रकोप होने के बाद कमजोर अवधि की वजह से निर्यात नरम है।

मार्च में रत्नाभूषण निर्यात गिरकर रह गया आधा

राजेश भयानी
मुंबई, 5 अप्रैल

कोविड-19 ने रत्नाभूषण उद्योग का भविष्य बिगाड़ दिया है जो पिछली कुछ तिमाहियों से परेशान चल रहा था। इस परेशानी की शुरुआत अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से हुई थी। बाद में आर्थिक मंदी और फिर हॉन्ग कॉन्ग के दंगों तथा अब कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन ने इस परेशानी को बढ़ा दिया।

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के शुरुआती अनुमान के अनुसार मार्च में इस क्षेत्र का निर्यात गिरकर आधा रह गया है। तराशे हीरे समेत कुल निर्यात मार्च में लुढ़ककर 1.5 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जबकि मार्च 2019 में यह 3.34 अरब डॉलर था। इस तरह इसमें 56.4 प्रतिशत गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 20 में इस क्षेत्र से होने वाला कुल निर्यात 11.33 प्रतिशत गिरकर 35.14 अरब डॉलर रहने का अनुमान है।

सूत्रों ने कहा कि सूरत हीरा प्रसंस्करण उद्योग को अपने सभी काम बंद करने पड़ गए हैं। अब उनके पास पिछले कुछ सप्ताह के दौरान प्रसंस्कृत किया गया बिना बिका हुआ स्टॉक ही बचा हुआ है और निकट भविष्य में नई मांग आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है क्योंकि वैश्विक बाजार में लॉकडाउन या अर्ध लॉकडाउन की स्थिति चल रही है।

हालांकि जब यह लॉकडाउन खत्म होगा और बाजार खुलेगा तो उद्योग को फिर से कारोबार करना होगा। अब तक दुनिया भर के उपभोक्ता अपने गैर-जरूरी व्यय में कटौती कर चुके हैं जिससे हीरा आभूषण खरीद पर असर पड़ रहा है। जब उद्योग में काम शुरू होगा तो सबसे बड़ा मसला ऋण जुटाना होगा। धन की आवश्यकता पहले की तुलना में सबसे महत्त्वपूर्ण होगी।

जीजेईपीसी के उपाध्यक्ष कोलिन शाह ने कहा कि हमने भारतीय रिजर्व बैंक से ब्याज दरों और निर्यात ऋण पर लागू मार्जिन में राहत देने, इस स्थिति में सभी क्षेत्रों के कारोबारियों और विनिर्माताओं को पांच प्रतिशत तक ब्याज अनुदान उपलब्ध कराने, पैकिंग क्रेडिट और निर्यात बिलों के लिए 90 से 180 दिनों की अवधि के लिए परमिट में विस्तार का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए क्षमता के पुनर्मूल्यांकन में समय लगेगा और कंसोर्टियम खाते में तो और ज्यादा समय लगेगा। इसलिए बैंकों द्वारा यह अतिरिक्त धनराशि आवेदन के सात दिनों के अंदर प्रदान की जाए। तभी इससे मदद मिलेगी। अगर उन्हें इसमें 90 दिन लगते हैं तो यह पूरा प्रयोजन बेकार हो जाएगा।

व्यापार गोष्ठी

कारोबार और रोजगार पर पड़ रही मार, आगे मुश्किल अपार

समुचित उपाय की जरूरत

कई सालों से मंदी से परेशान भारतीय अर्थव्यवस्था को अब लॉकडाउन ने त्रस्त कर दिया है। इसका सीधा असर पर्यटन उद्योग से लेकर विनिर्माण और खुदरा क्षेत्र पर भी देखा जा रहा है। इससे कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। अर्थव्यवस्था आज सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन हमें आने वाले समय की संभावनाओं पर भी नजर रखने की जरूरत है। दुनिया की तमाम कंपनियों ने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। लॉकडाउन से उबरने और आर्थिक विकास दर को संतुलित रखने के लिए कृषि व घरेलू उद्योग धंधे को विकसित करने के लिए समुचित और ठोस नीति की जरूरत है।

अंशुमान भारती
कोलकाता, पश्चिम बंगाल

कामगारों पर ज्यादा असर

लॉकडाउन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर पड़ने वाला है। आय स्रोत खत्म हो गए हैं। छोटे व्यवसायियों को निवेश के लिए पूंजी के अभाव से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आय में कमी से क्रय शक्ति में भारी कमी दिखाई देगी। नौकरी जाने के भय से लोग जमा पूंजी खर्च करना बंद कर सकते हैं जिससे बाजार में अन्य उपभोक्ता उत्पादों की मांग में कमी बनी रहेगी और वस्तुओं का उत्पादन भी घटेगा। रोजगार के अवसरों में कमी आएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। इसका दुष्प्रभाव कम करने लिए सरकार को रणनीति बनानी होगी।

ऋषभ देव पाण्डेय
जांजगीर चाम्पा, छत्तीसगढ़

अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा भारी

कोरोना का वार हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ेगा। कोरोना के कारण सरकार की आय और आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के सरकारी और निजी सभी साधन ठप हैं। यहां तक कि देश का सबसे बड़ा परिवहन नेटवर्क रेल यातायात भी बंद पड़ा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उद्योग-धंधे होते हैं। इसलिए उद्योग जगत और व्यापारी वर्ग को घबराहट में आकर न तो अपने दायरों को समेटने की गलती करनी चाहिए और न ही अपना घाटा पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों की छंटनी करने के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने उद्योग-धंधों और कारोबार को सुदृढ़ करने के प्रयास करने चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को उद्योग, धंधों और कारोबार की वित्तीय मदद करनी चाहिए। करों में कुछ समय तक भारी छूट देनी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

अधिक प्रयास की दरकार

लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर अभी सटीक असर का अनुमान लगा पाना मुश्किल है, परंतु ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो पिछले कई महीनों से आर्थिक संकुचन से विचलित हैं, वहां इसका बहुत असर नहीं होने वाला है, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिवेश से अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे उबरने में सरकार और समस्त आर्थिक तंत्र को अतिरिक्त प्रयास और सुधार की जरूरत होगी ।

शशांक श्रीवास्तव
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

नरम पड़ेगा कारोबार

लॉकडाउन के दौरान देश के संपन्न परिवार भी आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव से चिंतित हैं। लॉकडाउन की समय सीमा के कारण देशवासी भी पसोपेश की स्थिति में है। कोरोना के असर से आर्थिक गिरावट आने की आशंका है। सेवा एवं वस्तु उत्पादन, विपणन और बिक्री में काफी नरमी दिखाई दे रही है। व्यावसायिक गतिविधियों की रफ्तार धीमी पड गई है। सरकार को आर्थिक गिरावट कम करने के लिए आवश्यकतानुसार राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए और कम से कम उन कंपनियों को खोलने की छूट देनी चाहिए जो अपने कर्मचारी तथा उसके परिवार के रहने और खाने-पीने की व्यवस्था कर सकती हैं।

विनोद कुमार नाहटा
हाउडा, पश्चिम बंगाल

ई-कॉमर्स को बढ़ावा

लॉकडाउन से बाजार बंद होने का यह अर्थ नहीं है कि सारी व्यावसायिक व वाणिज्यिक गतिविधियां थम गई हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिये ऑनलाइन कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। कई कंपनियां घर से काम करने को बढ़ावा दे रही हैं। वेयरहाउस, गोदाम आदि से खुदरा विपणन के लिए किराना दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं घरों में पहुंच रही हैं जिससे रोजगार के कुछ अवसर बने हुए हैं। दिहाडी मजदूर, दैनिक वेतनभोगी, खुदरा कारोबारी, घरेलू नौकर-चाकर और नौकरी-पेशा वर्ग को सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।

रमेशचंद्र कर्नावट
इंदौर, मध्य प्रदेश

अर्थव्यवस्था को नुकसान

पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन से सब कुछ बंद हो गया। उत्पादन, विपणन, बिक्री, मानव संसाधन भर्ती और वित्तीय आदि सभी कार्य बंद हो गए हैं। इस लॉकडाउन से भारत को लगभग 120 अरब डॉलर का नुकसान होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। बार्कलेज, फिच और मूडीज आदि ने भारत की रेटिंग घटने का अनुमान लगाया है। देश को निश्चित ही आर्थिक तौर पर बड़ी हानि होने जा रही है।

डॉ. रसिकेश 'नवजात'
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

एमएसएमई पर बुरा असर

देशव्यापी लॉकडाउन से देश के सूक्ष्म, लघु और मझोले (एमएसएमई) कारोबार पर बुरा असर पड़ने लगा है। ग्लोबल अलायंस फॉर मास इंटरप्राइजेज के चेयरमैन रवि वेंकटेशन के मुताबिक अगर देश में लॉकडाउन चार से आठ हफ्तों तक बढ़ता है तो एक-चौथाई करीब 1.7 करोड़ एमएसएमई बंद हो जाएंगे। पर्यटन उद्योग पर भी लॉकडाउन का बहुत ज्यादा असर हुआ है जिससे नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। लॉकडाउन से आभूषण उद्योग को करीब सवा अरब डॉलर और विमानन उद्योग को कम से कम 63 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। दिहाड़ी मजदूरों के जीवन पर भी इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। अब सवाल यह है कि देश इस समस्या से कैसे उभरता है और अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर कैसे लाता है

साक्षी पांडेय
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

बकौल विश्लेषक

कारोबार पर पड़ेगी मार

लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को रोजाना हजारों करोड़ रुपये की चपत लगने से जीडीपी वृद्धि दर में भारी गिरावट आ सकती है। सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कारोबार को लेकर भी बड़ी चिंता है क्योंकि आयात और आपूर्ति शृंखला टूटने के कारण बेचने के लिए पर्याप्त माल का संकट पैदा हो सकता है। इसे पटरी पर आने में समय लग सकता है। श्रमिकों के पलायन से कारखानों और बाजारों में इनकी कमी से भी कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। लॉकडाउन अर्थव्यवस्था और कारोबारियों की कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है इसलिए सरकार को कर रियायत, सुगम व सस्ता कर्ज, लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के वेतन की क्षतिपूर्ति, किस्त टालने में लगने वाले ब्याज पर छूट आदि उपाय करने चाहिए। कर रिफंड भी कारोबारियों को जल्द दिए जाएं।

बातचीत : रामवीर सिंह गुर्जर

विजय प्रकाश जैन
राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल

घटेगी आर्थिक वृद्धि दर

देश में संपूर्ण लॉकडाउन से औद्योगिक उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा लगभग ठप पड़ा है। ओईसीडी के आकलन के अनुसार एक माह तक चलने वाले लॉकडाउन से जीडीपी वृद्धि दर में दो प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है। अगर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया तो यह काफी अधिक गिर जाएगी। लॉकडाउन से आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपूर्ति शृंखला तथा वितरण प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त है। अनौपचारिक क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जबकि देश के कुल उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 45 प्रतिशत है। सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, लेकिन हालिया स्थिति में यह नाकाफी है। स्थिति सामान्य होने पर चरणबद्ध तरीके से आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए।

बातचीत : वीरेश्वर तोमर

राकेश मोहन जोशी
अर्थशास्त्री एवं अध्यक्ष (अनुसंधान), भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

पुरस्कृत पत्र

बुरे दौर के आसार

1

कृतिका अग्रवाल
उज्जैन, मध्य प्रदेश

पुरस्कार राशि
500 रुपये

लॉकडाउन से समूची अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती नजर आ रही है। जीडीपी में 50 फीसदी योगदान करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र पर गहरा असर पड़ रहा है। वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5 से 5.2 प्रतिशत कर दिया गया है। लॉकडाउन का सबसे अधिक प्रभाव रोजगार पर पड़ेगा। लगभग 13.6 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है। अर्थव्यवस्था को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये की हानि संभावित है।

श्रेष्ठ पत्र

डॉ. हर्ष वर्धन कुमार
पटना, बिहार

रुकावट साबित होगा

लॉकडाउन अर्थव्यवस्था के लिए ब्रेकडाउन साबित हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को हर दिन 4.64 अरब डॉलर तथा 21 दिन की बंदी में जीडीपी को 98 अरब डॉलर का नुकसान होगा। एक्यूट रेटिंग्स के अनुसार वर्ष 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर दो से तीन प्रतिशत ही रहेगी। अर्थव्यवस्था के आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्र, कल्याणकारी योजनाओं और विकास पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

संध्या कुमारी
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

जीडीपी में गिरावट

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले 6.5 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था। एशिया-प्रशांत क्षेत्र को कोविड-19 से करीब 620 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़ेगा। छोटे कारखानों को नकदी की समस्या हो जाएगी।

डॉ. राम हर्ष गुप्ता
मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

रोजगार पर संकट

अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन का गहरा असर पड़ेगा। इसके बाद रोजगार की स्थिति और खराब होगी। बाजार में मांग न होने पर कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी करेंगी। भारत जैसे देश में, जहां पूंजीवाद नहीं है, बहुत-से सरकारी उपक्रमों पर इसका असर भले न पड़े, लेकिन यह निजी संगठनों की कमर तोड़ देगा। यह ऐसी स्थिति है जिसका खमियाजा सबको उठाना होगा।

... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की इस बार का विषय है **कोरोना की मार से कैसे बचें छोटे उद्योग ?**

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें: बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in

कोरोना पर मोदी ने की विपक्ष से बात

प्रणव, मनमोहन, देवेगौड़ा, सोनिया समेत मुख्यमंत्रियों से भी टेलीफोन पर बातचीत की

अर्चिस मोहन

देश में गंभीर स्वास्थ्य संकट की स्थिति बनने और 21 दिनों के लॉकडाउन के बावजूद विपक्षी नेताओं के साथ कोई बैठक न करने पर आलोचनाओं से घिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व राष्ट्रपतियों और कई विपक्षी नेताओं से फोन पर बात की। बुधवार को सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से मोदी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ दिनों में दुनिया के कई नेताओं के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी की है जिनमें शनिवार को ब्राजील के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत भी शामिल है।

ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्होंने मोदी से अनुरोध किया है कि वे मलेरियारोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट की आपूर्ति की इजाजत दें जिसका इस्तेमाल भारत में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकता है। भारत ने पिछले महीने दवा निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा और विपक्षी दलों के नेता प्रकाश सिंह बादल, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, एम के स्टालिन, अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव को फोन किया।

इस हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की थी। ममता बनर्जी उस बैठक में शामिल नहीं हुईं। हालांकि

- प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्रियों और पूर्व राष्ट्रपतियों से भी इस महामारी के सिलसिले में की है बात
- हाल में ट्रंप, एंजिला मर्केल, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स सहित दुनिया के कई नेताओं के साथ भी मोदी की हुई है बातचीत
- ट्रंप ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगी रोक हटाने को कहा

प्रधानमंत्री ने कुछ मौके पर मनमोहन सिंह से सलाह-मशविरा किया है लेकिन पिछले छह साल में उन्होंने शायद ही कभी सोनिया गांधी से संपर्क करने की कोशिश की हो। कई विपक्षी नेताओं ने रविवार रात को दीया जलाने की मोदी की अपील की आलोचना करते हुए कहा है कि जब देश को प्रभावी वित्तीय कार्ययोजना की जरूरत है तो मोदी 'प्रतीकात्मक' तरीकों से काम निपटा रहे हैं।

ट्रंप से मिला भरोसा

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान में मोदी ने कोविड-19 महामारी पर विचारों का आदान-प्रदान करते हुए इस बात पर सहमति जताई कि इस महामारी से मुकाबला करने के लिए भारत-अमेरिका साझेदारी की पूरी ताकत लगाई जाएगी। एक बयान में कहा गया है, 'दोनों नेताओं ने इस कठिन दौर में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और आयुर्वेद (पारंपरिक भारतीय जड़ी-बूटी आधारित चिकित्सा) के महत्त्व पर भी बात की।'

ट्रंप ने व्हाइट हाउस कोरोनावायरस टास्क फोर्स ब्रीफिंग में घोषणा की, 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज (शनिवार) बातचीत के बाद भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगी रोक हटाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।'

ट्रंप ने कहा, 'भारत यह दवा भारी मात्रा में बनाता है और उसे भी अपने करोड़ों लोगों के लिए इस दवा की जरूरत है। मलेरिया रोधी दवा हाड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को इलाज के लिए स्ट्रैटजिक नैशनल स्टॉकपाइल के जरिये जारी किया जाएगा। मैंने उनसे कहा है कि अगर वे हमारे ऑर्डर के मुताबिक उतनी ही मात्रा में दवा भेजते हैं तो मैं इसकी सराहना करूंगा।'

अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल पॉम्पियो ने पिछले सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कोरोनावायरस से निपटने के लिए अमेरिका और भारत के बीच लगातार सहयोग जारी रखने की अहमियत और वैश्विक दवा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के बारे में भी विचार-विमर्श किया।

ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर से बातचीत

प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेस्सियस बोलसोनारो के साथ भी टेलीफोन पर बातचीत की जिसमें दोनों नेताओं ने कोविड से उबरने के बाद एक नई मानव केंद्रित वैश्विक अवधारणा तैयार करने की जरूरत पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मोदी ने इस मुश्किल घड़ी में ब्राजील के राष्ट्रपति को हर संभव समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

प्रधानमंत्री ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पेरेज कास्टेजॉन के साथ भी बात की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने महामारी के कारण अपने घरों में बंद रह रहे लोगों के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योग और पारंपरिक जड़ी-बूटियों पर आधारित दवाओं की उपयोगिता पर सहमति जताते हुए इसे आसानी से उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हुई बात

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, जर्मनी की चांसलर एंजिला मर्केल, कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा अल-खालिद अल-हमद अल-सबा के साथ भी कोविड-19 महामारी से निपटने के मुद्दे पर टेलीफोन पर बातचीत की है।

एक बयान के अनुसार, 'जर्मनी की चांसलर ने इस बात पर मोदी के साथ सहमति जताई कि कोविड-19 महामारी आधुनिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है और इसने पूरे मानवता के साझा हितों पर केंद्रित वैश्वीकरण का एक नया नजरिया तैयार करने का मौका दिया है।

योगी ने 14 को लॉकडाउन खत्म होने के दिए संकेत

बीएस संवाददाता

लॉकडाउन बढ़ने की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके 14 अप्रैल के बाद खत्म हो जाने के संकेत दिए हैं। रविवार को प्रदेश के सांसदों, विधायकों व विधान परिषद के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि 21 दिनों की बंदी के बाद 15 अप्रैल से सब कुछ खुलने लगेगा। योगी ने विधायकों से बातचीत के दौरान कहा है कि उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि जब 15 अप्रैल को लॉकडाउन खुले तो भीड़-भाड़ न होने पाए और सोशल डिस्टैंसिंग का ठीक से पालन किया जाए।

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि वह अपने सुझाव दें कि लॉकडाउन के बाद सब कुछ कैसे खोला जाए और चरणबद्ध तरीका क्या हो। योगी से विधायकों की इस बातचीत की वीडियो क्लिप उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने जारी कर दी है। मुख्यमंत्री के इस संकेत के बाद यह साफ हो गया है कि 14 अप्रैल के बाद से कम से कम पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं रहेगा। प्रदेश सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी सिनेमा, शॉपिंग मॉल, स्कूल कॉलेज आदि कुछ दिन के लिए बंद रखे जाएंगे। बाजार व सरकारी कार्यालयों को सबसे पहले खोला जा सकता है।

आज शाम विभिन्न धर्मों के 377 गुरुओं से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भीड़ न जुटे इसके लिए सभी सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जनता को कोरोना से बचाव के लिए आगाह करते रहना और रोकथाम के लिए सजग करने की जिमेदारी धर्मगुरुओं को उठानी होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि केंद्र के स्तर पर भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर कोई साफ संकेत नहीं दिए गए हैं। बल्कि मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने तो स्कूल कॉलेज तक को 14 अप्रैल के बाद खोलने पर विचार करने को कहा है।

केंद्र ने कहा, ट्रक चालकों और श्रमिकों की आवाजाही तय की जाए

देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन के बीच केंद्र ने राज्यों से कहा कि राज्य के भीतर और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जरूरी सामानों को ले जाने के लिए चालकों को अपने घरों से ट्रक तक जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके साथ ही केंद्र न राज्यों से जरूरी सामानों के वितरण के लिए श्रमिकों को घर से कारखानों, लदान केंद्रों पर जाने की अनुमति देने को कहा।

उपभोक्ता मामलों के सचिव पचन कुमार अग्रवाल ने सभी राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि राज्य सरकार एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो जरूरी सामानों की सुगम आवाजाही के लिए राज्य पुलिस के साथ समन्वय करेंगे। इसके साथ ही नोडल अधिकारी राष्ट्रव्यापी आपूर्ति श्रृंखला में लगी कंपनियों को अधिकार पत्र जारी करेंगे, ताकि उनकी आवाजाही सुगम हो सके। लॉकडाउन के दौरान ट्रक चालकों को किसी तरह की समस्या नहीं हो इसके लिए एक चालक और एक सहयोगी को उनके आवास से ट्रक तक आने-जाने की सुविधा सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। अगर कोई ट्रक खाली चल रही हो तो बिल, ई-बिल आदि को चालक को अपने साथ रखना होगा जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा सकती है। कई कंपनियों ने श्रमिकों की कमी की शिकायत की है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन को फैक्टरियों में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-गॉव फाउंडेशन की मदद से ई-पास प्रणाली विकसित की है। इसकी मदद से अधिकृत कंपनियों द्वारा जारी पासों की संख्या पर नजर रखी जा सकती है। विभाग के सचिव ने कहा कि राज्य सरकार इस ई-पास समाधान को पास जारी करने के लिए उपयोग कर सकती है। *एजेंसी*

धारावी पर मंडराया कोरोना संकट का साया

पृष्ठ 1 का शेष

धारावी की तंग गलियों और बड़े परिवारों का एक छोटी सी जगह में रहना और कई लोग तो खुले गटर के पास भी रहते हैं। ऐसे में यहां साफ-सफाई बनाए रख पाना बृहन्मुंबई नगरपालिका (बीएमसी) के लिए एक सपना सरीखा है। जमीनी स्तर पर हालात से निपटने के लिए बीएमसी ने धारावी के सात वार्डों को कवर करते हुए सात शाखाएं बनाई हैं। प्रत्येक शाखा में लगभग 150 सफाई कर्मी हैं जो इस बस्ती की सड़कों की सफाई करने के साथ ही रोजाना दिन में दो बार कचरा इकट्ठा करते हैं। यहां हर दो दिन में कीटाणुनाशक का छिड़काव किया जाता है। धारावी में गरीबों के लिए मुफ्त भोजन वितरण सेवा देने में मदद करने वाले अधिवक्ता अख्तर खान कहते हैं कि यहां बड़ी तेजी से कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाता है। वह कहते हैं कि इन दिनों लोग अपने घरों में ज्यादा साफ सफाई कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन अब आगे देखना होगा कि यहां लोग कब तक ऐसा कर पाते हैं।खान जिस खाद्य वितरण सेवा से जुड़े हैं उसके जरिये रोजाना लगभग 100 से 150 लोगों के लिए एक बार मुफ्त

खाना दिया जाता है। वह कहते हैं, 'पिछले कुछ दिनों में विशेष रूप से लॉकडाउन शुरू होने के बाद से हमारे पास आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हम प्रतिदिन 200 से ज्यादा लोगों को खाना दे पाएंगे।'धारावी में काम करने वाले अधिकांश गैर सरकारी संगठन मानते हैं कि लोगों के बैंक खातों में पैसा डालने और लोगों को राशन की दुकानों पर एकत्र न होना पड़े इसके लिए लोगों के घरों में राशन वितरित करने की तत्काल जरूरत है क्योंकि ऐसा न होने से वायरस तेजी से फैल सकता है। कासारे कहते हैं, 'यह अच्छी बात है कि अमीर और गरीब लोग इस स्वास्थ्य संकट की घड़ी में सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं और वे पूरे मन से दान दे रहे हैं लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि यह पैसा वहां खर्च किया जाए जहां जरूरतमंद और गरीब लोग ज्यादा हैं।'

रेलवे भी जुटा आगे की कवायद में

रेलवे 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने के बाद ट्रेनों का परिचालन संभवत: शुरू होने से पहले तैयारियों में जुट गया है और कोरोनावायरस संक्रमण से निपटने को लेकर कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। इसके तहत यात्रियों द्वारा मास्क पहनना सुनिश्चित करने, यात्रा से पहले उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का उपयोग करने और ट्रेन में यात्रियों के बीच दूरी रखने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि, लॉकडाउन के मद्देनजर स्थगित की गई यात्री सेवाएं कब बहाल होंगी इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद यह चरणबद्ध तरीके से किए जाने की संभावना है।

अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन सेवाएं बहाल किए जाने के बारे में फैसला आगामी हफ्ते में लिए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि भारतीय रेल ने रेलवे बोर्ड से हर ट्रेन की विशेष मंजूरी मिलने पर ही सेवाएं बहाल करने के विकल्प पर चर्चा की है। जोन ने चरणबद्ध योजना के लिए बोर्ड को सुझाव उपलब्ध कराये हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यह संवेदनशील समय है और हम फिलहाल राजस्व अर्जित करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मुख्य जोर यात्री सुरक्षा पर और (कोरोना वायरस) महामारी के नहीं फैलने पर है। सरकार जब हरी झंडी दिखा देगी तब समय आने पर ट्रेनें चलेंगी। हालांकि अभी तक हमने कोई फैसला नहीं लिया है।' *भाषा*

शो जारी रखने की भारी चुनौती

लॉकडाउन से जनसंचार माध्यमों की मांग में अचानक तेजी आई है। टीवी चैनल, डीटीएच ऑपरेटर, स्ट्रीमिंग फर्में और मीडिया एवं मनोरंजन से जुड़ी दूसरी कंपनियां चुनौतियों के कैसे निपट रही हैं

वनिता कोहली-खांडेकर

गुरदीप खन्ना परेशान थीं। 82 साल की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी गुरदीप दिल्ली के रोहिणी इलाके में अकेले रहती हैं। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उनके बेटे ने उन्हें कुछ महीनों के लिए ग्रेटर नोएडा में अपने घर में चलकर रहने को कहा। उन्होंने साथ ही अपनी मां को सुझाव दिया कि वह टाटा स्काई का सेटटॉप बॉक्स भी अपने साथ ले चलें और उसे ग्रेटर नोएडा में अपने कमरे में लगे टीवी से जोड़ दें। उन्होंने 12 मार्च को ऐसा ही किया लेकिन उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला। 22 मार्च को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लागू किया गया और फिर 24 मार्च की मध्यरात्रि से देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा हुई तो गुरदीप की मुश्किलें बढ़ गई। उन्होंने सेटटॉप बॉक्स की गड़बड़ी को दूर करने के लिए कई बार कॉल किया और कई व्हाट्सऐप मैसेज भेजे लेकिन टाटा स्काई इंजीनियर भेजने में नाकाम रही। थकहारकर उन्होंने 28 मार्च को 6,148 करोड़ रुपये की इस कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी हरित नागपाल को अपनी समस्या के बारे में लिखा। अगले दिन यानी 29 मार्च को एक इंजीनियर ने उनसे फोन पर बात की और उन्हें अपना सेटटॉप बॉक्स दुरुस्त करने में मदद की। अब वह आराम से अपने पसंदीदा शो देख रही हैं। उन्हें अमेरिकाज गॉट टैलेंट, हॉलीवुड फिल्में और खेलों के कार्यक्रम बहुत पसंद हैं।

टाटा स्काई के देशभर में 1.80 करोड़ उपभोक्ता हैं और रोज उसे करीब एक लाख कॉल आती हैं। इनका बोझ कम करने के लिए कंपनी ने 14 सेवाओं को व्हाट्सऐप पर डाला है जिनमें चैनलों को जोड़ना और हटाना भी शामिल है। इसके बावजूद घर से काम कर रहे कंपनी के कॉल सेंटर एजेंट केवल 30 फीसदी डाइवर्टेड कॉल ही ले पा रहे हैं। नागपाल ने कहा, 'हम 50 से 60 फीसदी कॉल लेना चाहते हैं। फील्ड सर्विस के कुछ लोगों के बुजुर्गों का काम देखने के लिए लगाया गया है। उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। दस्ताने, मास्क और संक्रमण से बचाव के लिए दवा दी गई है। हम रोजाना 700 से 800 मामलों को ही देख पा रहे हैं जो केवल बुजुर्गों से ही जुड़े हैं। सामान्य दिनों में यह संख्या 4,000 से 5,000 होती है।' कंपनी के छतरपुर अपलिंक सेंटर में 35 और बेंगलूरु आईटी केंद्र में 15 कर्मचारी इस काम में जुटे हैं कि टाटा स्काई पर 600 चैनलों का निर्बाध प्रसारण होता रहे।

टाटा स्काई के देश भर में 1.80 करोड़ उपभोक्ता हैं और रोज उसे करीब एक लाख कॉल आती हैं

टाटा स्काई तो केवल उदाहरण है। देश की दर्जनों मीडिया कंपनियों को इन दिनों अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास ऐसे समय में दर्शकों की संख्या में बाढ़ आ गई है जब सामान्य कामकाज पर कई तरह की बंदिशें लगी हैं। पिछले साल यानी 2019 में 83.6 करोड़ से अधिक भारतीयों ने टीवी देखा, 39 करोड़ लोगों ने इंटरनेट पर खबरें देखीं, इतने ही लोगों ने अखबार पढ़ें और फिल्मों के एक अरब से अधिक टिकट बेचे गए। ये सामान्य वर्ष के आंकड़े हैं। अब अप्रैल 2020 है और लॉकडाउन के कारण देश के 1.3 अरब लोग अपने घरों तक ही सीमित हो गए हैं। ऐसे में खुद को व्यस्त रखने के लिए जनसंचार माध्यमों की मांग बहुत बढ़ गई है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के प्रकोप से पहले (11 से 31 जनवरी) की तुलना में कोविड-19 का खतरा बढ़ने के बाद (14 से 20 मार्च) टीवी देखने वालों की संख्या में 8 फीसदी का इजाफा हुआ है। देश में रोज टीवी देखने वालों की औसत संख्या 56 करोड़ से बढ़कर 59.2 करोड़ पहुंच गई है। कॉमस्कोर के आंकड़ों के मुताबिक खबरों से जुड़ी वेबसाइट और ऐप देखने वालों की संख्या में फरवरी की तुलना में मार्च में 61 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

देश में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए गए उपायों के कारण 1,82,000 करोड़ रुपये के भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग को कई तरह की चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में टीवी सिगनल का ट्रांसमिशन, ऑनलाइन शो की स्ट्रीमिंग, कार्यक्रमों का प्रसारण और रोज अखबार निकालना अपने आप में बड़ी चुनौती है। उनसे जुड़ी हर तरह की प्रक्रियाएं और संवाद बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हालांकि इस मुश्किल दौर में कामकाज जारी रखने के लिए कई दिलचस्प तरीके भी सामने आ रहे हैं। अखबारों के जरिये कोरोनावायरस का संक्रमण फैलने की आशंका

लॉकडाउन के बाद जनसंचार माध्यमों की मांग काफी बढ़ गई है

बढ़ रही है और यही वजह है कि डीबी कॉरपोरेशन (दैनिक भास्कर) जैसी अखबार निकालने वाली कुछ कंपनियां पूरी आपूर्ति श्रृंखला को सैनिटाइज कर रही हैं। लॉकडाउन के कारण घर-घर अखबार पहुंचाने में दिक्कत आ रही है और इसकी भरपाई के लिए कुछ अखबार एक महीने का ई-पेपर मुफ्त दे रहे हैं। पीवीआर ने अपने 2 करोड़ पंजीकृत उपभोक्ताओं के साथ निरंतर संवाद कर रही है ताकि वे ब्रांड से जुड़े रहें। मल्टीप्लैक्स के बंद होने के कारण दर्शक फिल्में नहीं देख पा रहे हैं। वायकॉम18 के 1,600 कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं और देशभर में फैले उसके दफ्तरों में केवल 20 लोग महत्त्वपूर्ण कामकाज संभाले हुए हैं। 3,667 करोड़ रुपये की इस कंपनी के समूह मुख्य कार्याधिकारी सुधांशु गुप्ता ने कहा, 'टीवी शो बनाने का काम 18-19 मार्च से बंद है। हमारे पास इस सप्ताह तक ही प्रसारण की सामग्री शेष है। उसके बाद हम पुराने कार्यक्रमों का ही प्रसारण करेंगे।' एपलॉज एंटरटेनमेंट के तैयार शो में से एक 'मनफोड़गंज की बिन्नी' हाल ही में एमएक्स प्लेयर पर रिलीज किया गया जबकि एक और शो 'हसमुख' इसी महीने बाद में नेटफ्लिक्स पर जारी होगा। तीन शो की आधी शूटिंग हुई है जबकि तीन में प्रोडक्शन के बाद का काम बाकी है। फिलहाल ये सभी बंद हैं। हालांकि लेखन और प्रसारक कंपनियों और ओटीटी को सुझाव भेजने का काम बदस्तूर जारी है। यह ऐसा काम है जो व्यक्तिगत या टीम स्तर पर दूर रहकर भी हो सकता है।

एपलॉज एंटरटेनमेंट के मुख्य कार्याधिकारी समीर नायर कहते हैं, 'अचानक हमें लग रहा है कि हमें मिलने की जरूरत नहीं है।' नागपाल ने कहा, 'मुझे हर हफ्ते पांच दिन काम पर जाने की क्या जरूरत है। मुझे 30 मिनट की बैठक के लिए दिल्ली या बेंगलूरु जाने की क्या जरूरत है। सरकारी बैठकें भी तो हो ही रही हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। इससे लागत में कमी आएगी और समय बचेगा।' वह टाटा स्काई द्वारा हाल में जारी की गई एक विज्ञापन फिल्म की तरफ इशारा करते हैं। इसमें कंपनी ने घोषणा की है कि शिक्षा, फिटनेस और कुकिंग आदि से संबंधित उसकी 11 सेवाएं एक महीने के लिए मुफ्त उपलब्ध रहेंगी। इसका निर्देशन फोन के जरिये किया गया और इसे विभिन्न शहरों में तीन दिन तक फिल्माया गया।

कामकाज के नए-नए तरीके वायकॉम18 और टाटा स्काई जैसी बड़ी कंपनियां या एपलॉज जैसी वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां अपना रही हैं। एपलॉज के पीछे कुमार मंगलम बिड़ला का हाथ है। लॉकडाउन के कारण मीडिया और मनोरंजन से जुड़ी कंपनियों को राजस्व और वृद्धि में 20 से 25 फीसदी नुकसान होने का अनुमान है जिससे उनसे जुड़ी छोटी कंपनियां भी प्रभावित होंगी। अगर यह संकट अप्रैल से आगे भी जारी रहता है तो इससे कई छोटी प्रोडक्शन कंपनियों और सिंगल स्क्रीन चलाने वाली कंपनियां बंद हो सकती हैं। दूसरी कंपनियां भी आननफानन में अपना कारोबार बेच सकती हैं। कुछ बड़ी कंपनियां अपनी छोटी आपूर्ति फर्मों और साझेदार कंपनियों की मदद कर रही हैं। उन्हें प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के राहत कोष के जरिये मदद दी जा रही है या बकाये का भुगतान किया जा रहा है ताकि वे अपने कर्मचारियों का वेतन दे सकें। दूसरी कई कंपनियां उन्हें सीधे तौर पर मदद कर रही हैं।

वत्स ने कहा, 'हमारे शो बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसों से हमने कहा है कि मुंबई में 30 हजार रुपये और मुंबई से बाहर 20 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में कोई कटौती नहीं होगी। इसके दायरे में 1,500 लोग आते हैं। इन लोगों के वेतन का 60 फीसदी हिस्सा हम वहन करेंगे और बाकी 40 फीसदी प्रोडक्शन हाउस देंगे।'

उम्मीद की जा रही है कि यह संकट मई-जून तक खत्म हो जाएगा। पीवीआर पिक्चर्स के मुख्य कार्याधिकारी कमल ज्ञानचंदानी ने कहा, 'दूसरी और तीसरी तिमाही में कई बड़ी फिल्में रिलीज होंगी। मांग में बढ़ोतरी का मतलब है कि सामान्य से ज्यादा सीटें भरी रहेंगी। हम यही उम्मीद कर रहे हैं।' लेकिन लाखों दर्शकों, उपभोक्ताओं, श्रोताओं और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों के लिए शो जारी रहना चाहिए।